पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 5 अंक 3 | इंदौर, सोमवार 15 मार्च से 21 मार्च 2010 | पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 सिद्धांत चिंतन नहीं-स्वार्थ पूर्ति चिंता

3 बजट में महंगाई बढ़ाने और भ्रष्टाचार से कमाई

4 भोपाल गैस-25वर्ष बाद भी धीमी मौत की कारक

5 मप्र लो.नि.वि. को बंद करने की साजिश

6 उपभोक्ताओं से बजट से शुरी लूट फिर भी प्रदेश में अंधेरा

7 मात्र 10% राजस्व ही आता है शासन के खाते में

केंद्रीय बजट 10-11 उन्नति के शिगूफे और लूट का मायाजाल

मध्यवर्गीय से चहूंदिशि वसूली

अंबानी का बजट, अंबानी का, अंबानी के लिए

नई दिल्ली। केंद्र में बैठी कांग्रेसी गिरोह की गिद्धों की फौज अपनी कमाई लूट और कमीशन खोरी की वसूली के लिए सब कुछ करती है, ये उसका इतिहास रहा है, वर्तमान 2010-11 के बजट ने उसे सिद्ध कर दिया है भविष्य का आंकलन बजट वाले दिन से ही डीजल-पेट्रोल की कीमतों में 5 से 8% की बढोतरी से रुपए 3/-प्रति लीटर, डीजल, पेट्रोल महंगा हो गया, बाकी सबकी कीमतें अब स्वयं ही आसमान छूने लगेंगी, 5% से 8% पेट्रोल डीजल की कीमतों की सीधी बढोतरी बाजार में आम उपभोक्ताओं को 10 से 20% तक हर वस्तुओं की कीमतों पर चिपकाकर वसूली जाएगी।

बजट की बारीकियों के विश्लेषण से पूर्व हम आपको बता दें अक्टूबर 09 से मुकेश अंबानी हर बुधवार को सुबह 10 से 7 बजे शाम तक प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर अपने लिए और उद्योग जगत से वसूली और कमीशन वसूलने के लिए उनके

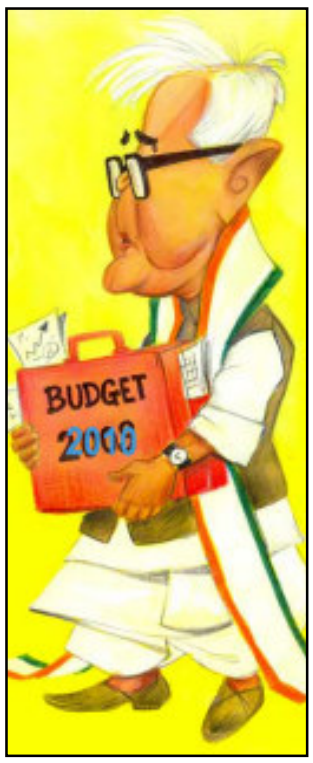

फायदे का बजट बना रहे थे, अर्थात यह बजट अंबानी का था, अंबानी के लिए था और अंबानी को ही इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, अर्थात पूंजीपतियों का बजट, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के फायदे के लिए ही पूर्णतः बनाया गया है।

रुपए 2000 से रुपए 44000/- प्रति माह कमाने वाले से लेकर चहुंदिशि लूट और वसूली ही होगी, उसे तत्काल में पेट्रोल डीजल पर रुपए 3 प्रतिलीटर सीधे ओ वाले के लिए चुकाना होंगे तो दूसरी तरफ दूध, गेहूं, चावल, दाल से लेकर सब्जियों पर भी इसकी कीमत चुकानी होगी।

समृद्धि और विकास के नाम पर संरचना तक विकास के नाम रुपए 1.73 लाख करोड़ और सामाजिक क्षेत्र में रुपए 1.38 लाख करोड़ बाजार में आएगा तो रुपए की कीमत गिरेगी और इतनेही धन से बाजार में आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी इससे भी गरीब और कम आय वाले मध्यमवर्गीय से ही धन वसूला जाएगा। रुपए 5000/- तक प्रतिमाह कमाने वाले को दाल-रोटी भी मुश्किल से ही मिल पाएगी। इसके विपरीत सारे फायदे उद्योग जगत ही डकार जाएगा।

समृद्धि विकास के संरचना तक कार्यों पर रुपए 1.73 लाख करोड़ रुपए में से रुपए 1 लाख करोड़ प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रधान, मुख्यसचिव और अंतिम बिन्दु तक बैठे अधिकारी ही डकार जाएंगे। अर्थात् विकास के नाम केवल सरकारी अधिकारियों, संबंधित विभाग के मंत्री को ही लाभ मिलेगा, जबकि वसूली आम आदमी की जेब से की जाएगी और की जा रही है। रुपए 1.38 लाख करोड़ सामाजिक क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इसमें सेभी रुपए 1 लाख करोड़ दिल्ली से लेकर अंतिम बिन्दु तक पहुंचते-पहुंचते कागजों पर खर्च कर डकार लिए जाएंगे और रुपए 38 हजार करोड़ ही लक्ष्य पर पहुंचेंगे।

ये जितना पैसे बाजार में आएगा उतनीही रुपए की कीमत गिरकर क्रयशक्ति कम करेगा, अर्थात उसकी तुलना में दुगुनी-तिगुनी तक बढ़ सकती है। जबकि मजदूरी दरें उस तुलना में 5 से 10% भी नहीं बढ़ेगी, अर्थात तब भूख से मरने वाले गरीबी रेखा से ऊपर और निम्न मध्यवर्गीय ही मरेगा।

बैंकिंग उद्योग को 16500 करोड़ क्यों दिया गया, जबकि पूरी बैंकिंग अध्यक्ष, **शेष पेज 4 पर**

झूठे आंकड़ों की बाजीगीरी म.प्र. बजट 2010-11

रुपए 30,000 करोड़ से ज्यादा हड़पने की व्यवस्था

संरचना विकास के नाम

रुपए 3220.46 करोड़ की व्यवस्था ऊर्जा विभाग को

जब वर्तमान जल विद्युत व ताप विद्युत परियोजना निजी व शासकीय उपक्रम के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं जिसमें शासन को धन देने की आवश्यकता कहां पर है, बेशक अनुदान के बहाने अपनी हिस्सेदारी, उन कंपनियों में जो जल और ताप विद्युत ऊर्जा की उत्पादन इकाईयां स्थापित कर रही हैं बनाने के लिए सरकारी पैसा जनता का और हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग, मंत्री, मुख्यमंत्री, ऊर्जा सचिव, मुख्य सचिव की भ्रष्टाचार का ये निराला अंदाज पुराना और उच्च स्तरीय है।

विद्युत खरीदी के मामले में भी अपने हिस्से की एनटीपीसी, एन.एल.डीसी, छत्तीसगढ़ से सस्ती बिजली तो ये हरामखोर विद्युत वितरण कंपनियों और विद्युत परिषण वाले खरीदते नहीं, साथ अपनी जल और ताप विद्युत सस्ती बेचते और अन्य राज्यों को अंतरण कर देते हैं, फिर ऊंचीदरों पर कमीशन खाने के लिए टाटा पावर व अन्य से खरीदते हैं। दरों के अंतर में अरबों रुपए का कमीशन डकारते हैं। इनकी ताप विद्युत की अनेकों इकाइयां जानबूझ कर खराब कर बंद करके रखी हुई है। येही विद्युत आबंटन के रुपए 3220 करोड़ का बजट, फिर एमडी के रूप में बैठे सारे आईएएस शूकरों को धन से मतलब है बूढ़ा मरे या जवान माल बाप का तो नहीं फिर सरकारी धन पर तो सबकी निगाहें हैं ही वरन शासकीय विभाग डकैतों की ही अड्डे हैं।

रुपए 2869 करोड़ सड़क विकास

म.प्र. लोक निर्माण विभाग की जब सारी सड़कें आजमगढ़ के आतंकी सुलेमान ने चीन कर म.प्र. सड़क विकास निगम के अधिग्रहित कर ली है। एक तरफ वो हरामखोर लोक निर्माण विभाग में आतंक बरपा कर लोक निर्माण विभाग के 15 संभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के अप्रैल 10 से बंद कर रहा है। तो दूसरी तरफ लोक निर्माण पर आतंक बरपा कर सारे कार्यों के अलग मुख्य अभियंताओं को भोपाल में बैठाकर सारा धन डकारने के लिए व्यवस्था कर रहा है। **शेष पेज 3 पर**

पुराना हटाकर, बहुराष्ट्रीय कं. के लिए नया कानून

कांग्रेस सरकार के गिद्दों को जनता की समृद्धि और खुशी से सख्त नफरत है, ये पुराने समय में दमनकारी राजाओं से भी ज्यादा नीचमासिकता के तो राक्षस है, जिन्हें जनता का अर्थ हर 5 वर्ष में बस वोटों की गिनती से है, चुनाव जीतने से लेकर अगले चुनाव होने के 6 माह पूर्व तक आम जनता का अगर इनका बस चले तो पूरा खून चूस कर अनुदान के पानी में जनता को जिंदा रखें और मुफ्त की हवा से चलती सांसों पर भी ये राक्षसों का टोला उचित मूल्य की दुकानों में खड़ा कर हवा की भी राशनिंग कर कमाई करने लगे।

खाद्य सुरक्षा के नाम बहुराष्ट्रीय कं. की कमाई-२

इसके पूर्व जनता को ये बता दें कि इनके सत्ता में आने के लिए इन्हें जनता से नहीं इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की जालसाजी से जीत मिली है, जिसकी तैयारी उस जलगांव की मिस जलगांवकर उर्फ प्रतिभा पाटिल **शेष पेज 2 पर**

ब्राजील और चिली में ८.८ का भूकंप

सुनामी का प्रभाव जापान तक

शनिवार 27 फरवरी 10 को ब्राजील के चिली में आए 8-8 तीव्रता के भूकंप से 3000 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए, चिली की राष्ट्रपति मिशेल बासलेट ने बताया कि चिली के तट से 660 किमी दूर आबादी वाले बासलेट राबिन्स क्रूसो द्वीप पर विशाल लहरें रात्रि के अंदकार में जब सप्ताहांत की मौज मस्ती में नाइट क्लबों में व्यस्थ थे तभी उठी समुद्र में तटों के किनारी पर गहरे पानी में हारपून मिसाइलोंसे नीचे जमीन के 500 से 1000 मी. अंदर घूस कर परमाणुवीय न्यूक्लियर मिसाइलें फोड़ने पर जमीन में चट्टानों के फटने से तल पर भारी भूकंप और जल में गहरे अचानक विस्फोट से 500 से 500 किमी प्रति घंटे की इन लहरों ने हजारों किमी दूर जापान तक कहर बरपाया।

अमेरिका द्वारा नष्ट होती परमाणु मिसाइल परीक्षण

सुनामी का अर्थ है - टी से टेस्ट, यू से अनाक्लियर्ड, एन से न्यूक्लियर, ए से एटमिक, एम से मासिक, आई से इपेक्टस अर्थात जीवन समाप्त होने वाली साफ किए जाने वाले समय बाधित परमाणु और नाभिकीय बमों की जांच या परीक्षण और उसका वृहत प्रभाव **शेष पेज 2 पर**

सम्पादकीय

सिद्धांत चिंतन नहीं- स्वार्थ पूर्ति चिंता

भारत भूमि सभी सुख, सम्पदाओं, कृषि की उर्वरता से परिपूर्ण है, इसकी यही परिपूर्णता एक तरफ सौभाग्य के कारण रही तो दूसरी तरफ घोर दुर्भाग्य का कारण और गुलाम मानसिकता, घोर स्वार्थीयों की भी उर्वरता भी इसी भूमि का दुर्गुण भी रहा, यही सुख सम्पन्नता की उर्वरता ने यहां पर जन्म लेने वालों को न केवल घोर आलसी, स्वार्थी और मतलब परस्त भी बना दिया है, यही स्वार्थ मतलब परस्तों ने सत्ता के शीर्ष पर बैठकर अपनी अय्याशी और मौजमस्ती के लिए सहस्त्रों वर्षों से आक्रांताओं को आमंत्रित कर पैर जमाने और राज करने का भी मौका दिया, आमजन सहस्त्रों वर्षों से आक्रांताओं, जिसमें अलेब्जेंडर, सेल्यूकस से लेकर हूणों, शको, मुगलों, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज से लेकर अंग्रेजों को साठ पूर्व तक जमाए रखा, यदि ये ऋषि मुनियों, देवताओं की भूमि रही है तो दानवों की भी यही भूमि रही है।

वर्तमान में भी यही स्वार्थी घोर मतलब परस्त मानसिकता न केवल सत्ताधीशों, वरन जनता में भी कूट-कूट कर भरी हुई है। पड़ोसी के जलते घर में आए आंख में आंसू देखकर हम मुस्कुराते हैं जबकि उसकी घर की आगह में लपेट लेगी पता ही नहीं लगता कि मुस्कुराते- मुस्कुराते कब आंसू आने लगे, यही हाल हमारा हमारे मोहल्ले, समाज से लेकर राष्ट्र के प्रति भी रहता है। इसका फायदा ही विदशियों ने उठाया और राज्य किया, कुछ छोड़कर चले गए और कुछ आक्रांताओं ने इसी धरती की स्त्रीयों को छुड़ाकर उनसे स.... विस्तार किया और जम गए, ये वही नारी है जिसे हमने एक तरफ देवी बनाकर पूजा तो दूसरी तरफ भोग्या बनाकर भोगने के लिए कैद करके रखा, स्वाभाविक था वही अपनी संतति को एक जुटता और स्वाभिमान का पाठ नहीं पढ़ा पाई, जो हमारी गुलामी का भी मूल कारण रही, यह इतिहास वर्तमान में भी सत्ताधीशों की सत्ता में बैठकर मौज मस्ती और देश की सत्ता को नोंचकर भ्रष्टाचार से या शिष्टाचार से अपने लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए धन सम्पत्ति के बंदोबस्त करने से ही स्पष्ट होता है।

भारत की राजनीतिक पार्टीयों में राष्ट्र प्रेम, स्वाभाविमान न तो स्वयं सीखता है न राष्ट्र की जनता को सिखाता है, उसे तो तत्काल में अमेरिका से भीख मिल रही है तो ले, लो जनता के काम आए न आए जनहित में उपयोग करो न करो डकार तो लो जनता को ही भुगतान करना है कि दम पर कर्ज लेकर घी पीने के आदी हो चुके हैं। भाजपा जो अपने आपको सिद्धांतों की पार्टी कहती है अभी हाल में ही हुए 17,18, 19 फरवरी को हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में सामने आया सच यह था कि किसी को भी इस राष्ट्र की जनता की चिंता नहीं थी, जबकि इस देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 जैसे गरीबों से लेकर मध्यमवर्गीय लोगों को बेरोजगार करने और उनके मुंह से रोटी का निवाला छीनने, बेरोजगार करने का पूरा षड्यंत्र 1 अप्रैल 10 से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही जनता के वर्तमान और भविष्य के जीवन को संवारने, उठाने और समृद्ध राष्ट्र बनाने का भी न सही वास्तविक, परंतु मानसिक व सैद्धांतिक चिंतन भी नहीं था। सबको चिंता थी तो 10% वोटों को कैसे बढ़ाया जाए जनता में अपने संघर्षशील का प्रमाण देने के लिए महंगाई और नक्सलवाद का सहारा लेकर जुझारू छवि का प्रदर्शन कर जनता के दिलों दिमाग में उतरने और आने वाले समय में 10% ज्यादा वोट कबाड़ कर सत्ता हासिल कैसे की जाए और अपने स्वार्थों की पूर्ति की जाए।

भाजपा सच अपने आप को जमीन से जुड़ी पार्टी बताती है तो कभी इन दिग्गज धूर्तों ने इस बात का सैद्धांतिक चिंतन भी किया कि कैसे हर हाथ को काम, हर पेट को दो वक्त की रोटी और रहने के लिए छत की व्यवस्था करते हुए राष्ट्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बनाया जाए। राष्ट्र की वर्तमान प्राकृतिक सम्पदाओं के न्यूनतम दोहन से अधिकतम लाभ प्राप्त कर जनता को कैसे सम्पन्न और विश्व में अग्रणी बनाया जाए। राष्ट्र की जनता को पूंजीपतियों के शोषण, सफेद पोश डकैतों से सुरक्षित रखते हुए विश्व की प्रगति में हमारी जनता कदम से कदम मिला कर कैसे चल सकेगी। राष्ट्र की प्राकृतिक सम्पदाओं विदेशी हाथों से जाने से कैसे रोका जाए, राष्ट्र की परंपराओं, संस्कृतियों को पुर्नजीवित कर आधुनिक दृष्टि कोण से परिभाषित कर समाज और राष्ट्र के पश्चिमी अंधानुकरण को रोक कर नग्नता, तलाक यौन उच्छृश्रृंखलता की तरफ जाती पीढ़ी को कैसे संस्कारित कर विकसित किया जाए, अर्थात ये धार्मिक और हिन्दुवादी धार्मिक राजनीतिक पार्टी होने राम का नाम लेकर सत्ता हथियाने वाली पार्टी का अपनी पितृ संस्था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरह के नारे एक जुट हो, बढ़े चलों में भी बुराइ क्या है, इसके विपरीत ये भाजपाई भी अमेरिका की कठपुतली बन नाचने तैयार हैं जब सत्ता में थे तो ये भी अमेरिकी उसकी बहुराष्ट्रीय और देशी पूंजीपतियों की गागरौंनी बोलते थे। इसलिए इनके पास भी भ्रष्टाचार और राष्ट्र बेच धन कमाने के विकल्पों का ये भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं। इनके पास राष्ट्र की श्रेष्ठता, जनता की समृद्धि का कोई सैद्धांतिक चिंतन नहीं, जो इस उर्वरा भारत भूमि का वर्चस्व विश्व में स्थापित कर राष्ट्रीयता स्थापित कर स्वाभिमान से जीना सिखाए।

पुराना हटाकर ...

पेज एक का शेष

मोटे कमीशन के लिए सारा खाद्य उद्योग आईटीसी और रिलायंस के हवाले

के राष्ट्रपति बनाने से शुरू कर दी थी, बाद में चावला जैसे जालसाज को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का षडयंत्र भी इसी जालसाजी पूर्ण तरीके सेचुनाव जीतने का अहम हिस्सा थी, जिसे समयमाया के पाठकों को मार्च 09 में ही जनता के सामने रख दिया था, जहां तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा के लाल को स्वप्न में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आने लगी थी इसलिए तो अपने आपको कृष्ण समझ पांडवों के रथ पर सवाल हो जमीन छोड़ चुके थे। उन्हें इन जालसाजियों की भनक होने के बाद भी वायुमार्ग से सिंहासन के स्वप्न में लीन थे, जिसने न भाजपा को वरन जनता को भी ये दिन दिखा दिए, अभी तो 4 वर्ष बाकी है देखिए आगे-आगे होता है क्या?

इस अधिनियम की व्याख्या से पूर्व आपको भारत में जनता के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने, मांगी गई या बताई गई खाद्य वस्तुओं की कीमत के बदल बेचे जाने वाले पदार्थों में गड़बड़ रोकने के लिए, भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 लागू था, जो वर्तमान में लागू किएजाने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से न केवल बेहतर था, वरन सरल होने के साथ ही उत्पादक, विक्रेता के लिए अर्थदंड के साथ कारगार की भी पूर्ण व्यवस्था थी, जिससे खाद्य प्रसंस्करणकर्ता या उत्पादक, विक्रेता को जेल का भय होने से मिलावट पर नियंत्रण था, जिससे बहुराष्ट्रीय कं. की मनमानी नहीं चल पाती थी, पहले तो इन बहुराष्ट्रीय कं. जिसमें पेप्सी, कोकाकोला, पारले जैसे हलके पेय पदार्थों का व्यवसाय करने वाली कं. भी घबराती थीं, इनके कीटनाशकों के प्रयोग से पानी साफ करने की 2005-06 की घटना ने जब हंगामा मचाया तो इन हरामखोरों ने कीटनाशकों अहानिकारक मान उक्त अधिनियम में अरबों रु. बांटकर न केवल संशोदन करवा लिया वरन अपने व्यवसाय को, जनता को जहर पिवाने, उससे होने वाले नुकसान और जनता की मौतों के बदले इन्हें न केवल सजा न हो और दोष सिद्ध न किया जा सके। आसानी से नए अधिनियम 2006 में पूरी अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था भी करवा ली, लगे हाथों इस देश में करोड़ों की संख्या में व्यवसाय करने वाले लोगों से भी व्यापार छीनने, बाजारों, मंडियों की व्यवस्था को समाप्त कर एकाधिकार स्थापित करने का भी काम कर डाला, ताकि खेतों से माल उठाने से लेकर उपभोक्ता तक माल पेक करवाकर बेचने में ये सैकड़ों गुना से लेकर हजारों गुना लाभ प्राप्त करने में भी कोई परेशानी न उठानी पड़े।

आखिर सत्ताधीश गिद्धों ने इतना बड़ा फेरबदल क्यों और किस लिए किया? सीधा सा कारण है, कि जब ये रिलायंस, आईटीसी, मैकडोनाल्ड, हिन्दुस्तान लीवर, नेस्ले, टाटा, पारले जब पूरे देश के खाद्य सामग्री व्यवसाय पूरा अपने हाथ में ले लेंगी, बदले में मोटा कमीशन भी डिब्बा बंद नीचे से ऊप तक सबको बांटेंगे। इस तथ्य का एक छोटा सा उदाहरण टाटा के आयोडिन नमक को देखें, इस राष्ट्र की 120 करोड़ की आबादी के मात्र 30 लाख लोग जिसमें छत्तीसगढ़ के 2-3 जिलों के कुछ गांवों में, हिमालय की तराई के लगभग 20 लाख लोग को घेंघा रोग जोवहां के पानी के कारण होता है, को आयोडीन की जरूरत होती है, जो नमक के माध्यम से वहां के क्षेत्रीय व्यापारियों को बेचना चाहिए। इस धूर्त रतन टाटा ने उस समय मंत्रालय में पैसा बांटकर आयोडीन नमक कानून ही बनवा डाला, फिर विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि नमक से आयोडीन उड़ जाता है, दूसरा आयोडीन की अधिकता से दांतों पर धब्बे, रक्त शिराओं केआंतरिक भागों पर घातक असर पड़ने से कमजोर होकर फूटने तक की अवस्था आ जाती है, इसके विपरीत टाटा पिछले 4 वर्षों से पूरे देश के नमक पर एकाधिकार कर आयोडीन के तड़के के नाम पर अरबों रु. कमा रहा है। 10 से 20 प्रतिशत मंत्रालयों को खिलाकर देख की 120-119 करोड़ 70 लाख आबादी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अब ऐसा खिलवाड़ नमक, तेल, शकर, गेहूं, दाल, चावल से लेकर खाद्य तेलों, मसालों, सूखे मेवों, मिठाई, नमकीन आदि हर खाद्य पदार्थ में पैकेट बंद के नाम पर खुले में होगा, जैसे पेप्सी, कोक से बिस्कुट, चाकलेटों, हिन्दुस्तान लीवर, आईटीसी के मसानों तक में हो रहा है। अब ये हरामखोर हल्दी में खुले में 10प्रतिशत तक चावल की भूसी कानूनन मिला रहे हैं।

भारत में भारतीय एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यावसायिक गतिविधि अधिनियम 1971 से लागू है। इसके विपरीत टाटा अपना एकाधिकारी व्यवसाय कर रहा है, पर किसी ने भी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं की, वहीं अधिनियम में भी यह नया कानून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 के ठीक विपरीत कार्य करेगा, आईटीसी की चौपाल, रिलायंस की हरियाली अब किसानों के खेतों से सब्जी-भाजी से लेकर सभी अनाज दलहन, तिलहन भी खरीद कर अपने मनमाने भावों में इस माल को ऊंची कीमतों पर विदेशों में बेचेंगे और वहां से सड़ा गेहूं, तेल, शकर, चावल आयात कर यहां के जानवरों को परोसेंगे, जो अभी सरकार कर रही है कांग्रेसी गिद्धों की और इनसे करवाकर अरबों रु. का कमीशन चुपचाप डकार रही है। दूसरा यदि प्रसंवर्धन करेंगे तो मिलावटी कानूनन पेककर बेचेंगे, लिखेंगे कुछ और होगा कुछ जिसे सिद्ध करने में पीढ़ियां गुजर जाएगी। यदि उस जहर या मिलावट से हजारों लोग मर भी जाएंगे तो अंतिम सीमा रु. 51 लाख का भुगतान कर दिया जाएगा, वह भी उस खाद्य समिति और उसके अलग न्यायालय ने स्वीकृत किया तो वरन पैदा ही मरने के लिए हुआ था, मर गया तो मर गया, क्या करें, हम, क्यों?

इस अधिनियम का दानवी रूप 1 अप्रैल 2010 से लागू होने के बाद सही ढंग 2011 में आना शुरू होगा। इसके पीड़ितों ने अगर आंदोलन नहीं किया तो पूरे रूप में प्रकट होने म 2015तक का समय लगेगा, इसके बाद किसान पूरे देश में अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनकर इस ब्रिटिश टोबेको कं. की सहायक इंडियन टोबेको कं. के होंगे सारे खेत चाहे पट्टे के माध्यम से किराये के माध्यम से या किसानों के कर्ज में में डूबकर गंवा देने के माध्यम से, रिलायंस फ्रेश ने सब्जी-भाजी तक पर कब्जा कर लिया है, स्वाभाविक था सब्जी मंडियों पर, ठेलों पर सब्जी बेंचने वालों पर असर पड़ा, अब जब किसान के खेतों से ही सब खरीदा जाएगा तो ये सरकारी मंडिया अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी आदि लेकर मंडी या बाजार जाने की बात तो समाप्त हो गई, तो मप्र की मंडियों में बैठे व्यापारी, आढतियों के साथ मंडियों के भी लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी प्रकार लाखों किराना के शोक व फूटकर व्यवसायी भी बेरोजगार हो जाएंगे, पूरे देश में करोड़ों लोग खाद्य व्यवसाय से जुड़े भी बेरोजगार हो जाएंगे फिर कचोरी, पकोड़ी, चाट, मिठाई, नमकीन से लेकर चाय तक सिर्फ बहुराष्ट्रीय कं. की केंटीनों, रेस्त्रां, होटलों, शापिंग माल्स में ही मिलेगा और यह सब नहीं वरना पिज्जा, हॉटडाग मिलेंगे अर्थात हमारी पारंपरिक मिठाइयों, नमकीनों का एकदम सफाया हो जाएगा, सारी कहानी मोटे कमीशन और जनता को नोंचने और बर्बाद करने की है। ऐसे होगी खाद्य सुरक्षा के नाम पर मोटी कमाई की सुरक्षा।

सुनामी का प्रभाव...

पेज एक का शेष

शैतान सुनामी के नाम पर बरपा रहा है कहर- दुनिया में

कार्यक्रम क़ा नाम ही सुनामी है।

आखिर क्या किया जाए हजारों परमाणु और नाभिकीय बमों का जो 1970, 1980 या 1990 से बने रखे हैं। उनकी कार्यक्षमता की आयु या समय पूरा हो चुका है। उन्हेंकहां फैंका या दफनाया जाए। कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि वो अमेरिका, रूस व सभी परमाणु और न्यूक्लियर बमों से युक्त या शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की सेनाओं के लिए समस्त बन चुके हैं। युद्ध की परिस्थितियां बनते-बनते बिगड़ जाती है। आतंकवाद जैसे आखिरी हथियार भी बदनामी ज्यादा देतेऔर काम बहुत थोड़ा सा होता है। तो जो हथियार बम गोला, बारूद, मिसाइलें लड़ाकू जहाज, विमान हक पोत, पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां तक केवल अभ्यास ही अभ्यास में नष्ट हो रही हैं उनकी कार्य संचालन क्षमता से ज्यादा का कार्य लेने के बाद कबाड़े को भी कहां फेंका जाए। उल्टे ही उनका उपयोग उन पाले और विकसित किए आतंकी बिच्छुओं नेकर लिया हो उनकी स्वयं की जान को लेने देने पड़ जाएंगे।

अंत में उनको नष्ट करने के बहाने ऊपर से टपकाने की बजाय रात्रि के अंधकार में छुट्टियों को सुबह होने से पहले तटों में गहरे नीचे से हारपून मिसाइलें जो कि घूमते हुए लक्ष्य भेदन करती है सामने ड्रिलिंग बोर से छेद कर चट्टानों की ठोस पर्तों के बीच परमाणु या नाभिकीय बमों के विस्फोट किए जाएं तो एक तरफ ऐसे ऐसे बमों से छुटकारा मिलेगा, दूसरा उसका परीक्षण भी हो जाएगा, तीसरा सहायता और पुनर्निर्माण के बहाने उस राष्ट्र में घुसने, वहां पैर जमाने वहां की जनता से सम्पर्क बढ़ाने, व्यवहार, रहन सहन व अन्य गतिविधियों को जानने, वहां रहकर वहां की औरतों से यौनाचार कर अपनी वंशवृद्धि और संसतिफैलाने का मौका भी मिलेगा साथ ही अपनी दवाइयों के परीक्षण, उपयोग, बिक्री का भी मौका मिलने के साथ समय बाधित होती सामग्री भी खाई जा सकेगी।

दहशत का कहर बरपाया जा सकेगा, इससे अपना शक्ति प्रदर्शन होगा, सहायता के बहाने अपनी दरियादिली, महानता, दयालुता का प्रदर्शन कर दुनिया की टीवी चैनलों पर दिखा कर विश्व की जनता के दिलों में सहानुभूतिपूर्ण तरीके से स्थान पा सकेंगे। जनता भी कम होगी। 26-12-04 को हिन्द महासागर में इंडोनेशिया मलाया, सुमात्रा, थाईलैंड के तटीय क्षेत्रों में भी 5 से 10 बम फोड़कर जिस सुनामी की नौटंकी की गई थी उसका प्रभाव भी आस्ट्रेलिया से लेकर भारत के दक्षिण, पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों को बीस से 30 किमी तक अंदर कहर ढाया था, जिसमें भारत के 28 से 30 हजार गांव बह गए थे। लगभग 1 से डेढ़ करोड़ लोग मारे गए थे, जबकि इंडोनेशिया, थाईलैंड, सुमात्रा, मलाया में 40 से 50 लाख, बंगला देश में भी 10 से 15 लाख लोग समुद्री लहरों में समा गए थे। वहां भी क्रिसमस की छुट्टी के बाद रविवार की छुट्टी थी। हाल ही में फरवरी 10 में आए हेती के भूकंप भी उसी का परिणाम था। इन सभी भूकंपों की आप्राकृतिक होने के सभी पूर्व और पश्चात प्रभाव जो सामने आते हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि ये परमाणु और नाभिकीय बमों के परीक्षण के परिणाम ही हैं। प्राकृतिक भूकंपों में भी प्राकृतिक इतनेकहर नहीं ढाती दूसरे प्राकृतिक भूकंपों की मनुष्यों को पुर्वाभास हो न हो परंतु सभी प्राकृतिक वन्य प्राणियों, घरेलू पशुओं को इन बातों का पूर्ण अहसासहो जाता है। धरती पर भूकंप आते हैं, प्राकृतिक समुद्री तूफानों का अहसास प्राकृतिक हवा के दबाव बादलों के रुख और समुद्री जीवोंन का आप्राकृतिक भागदौड़ और हलचल समुद्री तूफानों जिनकी अधिकतम गति 50 से 300 कि.मी. प्रति घंटा तक ही होती है। जब 500 से 5000 किमी प्रतिघंटे की लहरें हो तो पाठक स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, या क्या हुआ है।

संकर प्रजाति का इतिहास रहा है, वह क्रूर, बेरहम, चालाक, मक्कार, धूर्तों की शातिर कौम होती है, अमेरिका पूरा देश संकर प्रजाति का ही है। मूल प्रजाति का इतिहास रहा है। प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण में प्रकृति के निकट रहकर प्राकृतिक तरीकों से जीवन जीना चाहे वो भारतीय आदिवासी हो, अमेरिकी रेड इंडियन आस्ट्रेलियाई चरवाहे, अफ्रीकी काले फिर अमेरिका का 100 वर्ष पुराना इतिहास उसकी कारगुजारियां विश्व पर गुंडागर्दी, नोंच खसोंट, कभी बीमारियों की दहशत, कभी एड्स, कभी हेपेटाइटिस, कभी स्वाइन फ्लू, फैलाकर अपनी दवाइयों, टीकों, कंडोम पर हजारों गुना लाभ कमाने के लिए भ्रम फैलाकर कमाई करता है तो कभी खेती के लिए बीटी, जीएम. कपास, टमाटर, भटे, गोभी, मटर, सोयाबीन, पपीते, केले, बेचकर अरबों रुपए कमाता है। हथियार बैचने के लिए तालिबान, लश्करे-तैयबा, हिजबुल से आतंक फैलाकर लड़ाई लड़वाता है। कभी सुनामी लाकर कहर ढाता है। क्यों चुप है दुनिया के दिग्गज, उपग्रहों से प्राप्त चित्रों को विश्लेषण क्यों नहीं करते। सबको समझ में आ रहा है पर कोई भी आका के सामने मुंह नहीं खोल पा रहा है।

बजट में महंगाई बढ़ाने और भ्रष्टाचार से कमाई

25/2/10 को विधानसभा से प्राप्त प्रेसनोट का विश्लेषण

पेज एक का शेष

जब सारे राज्य के मुख्य मार्गों को सविनि में अधिग्रहित कर ली, अन्य मार्गों पर एडीबी से ऋण लेकर कार्य करवाया जा रहा है। उसमें भी काम कम पैसा ज्यादा हजम करने का आतंक है। तो 2869 करोड़ का बजट कहां खर्च किया जाएगा?

यहां बैठे प्रधान सचिव, सचिव और मुख्य सचिव हरामखोर जानबूझकर 20-30 वर्षों से बैठे डिग्रीधरी तक को उपअभियंताओं से लेकर सहा. यंत्रियोंका यंत्रीयों, अधीण यंत्रीयों तक की पदोन्नतियां नहीं कर रहे हैं, ताकि ये आतंकी आतंक मचाकर प्रमुख अभियंता के पद पर भी आई.ए.एस. को बैठाकर धन हजम कर सकें। जिस 3316 किमी सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन की बजट में व्यवस्था की है वो सब अपने वलन केही इंजीनियरों को ही मिलेगा, धन जो आसानी से बंदरबांट कर सकें।

यहां 20 से 30 वर्षों से बैठे अभियंताओं को जानबूझकर इसलिए ही सड़ाया जा रहा है, एक ही पद पर ताकि ये अपने आतंक के चलते अपनी सारी कारगुजारियों करते रहें इन हरामखोर सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य और मुख्यमंत्री से धन हड़पने के बारे में चू-चपड़ नहीं कर सके। इस विभाग में भी अभियंताओं से लेकर बाबुओं तक की हर कार्यालय में भारी कमी है। सन 88 से यहां भी भर्ती नहीं हुई है। पर किसी भी श्वान को विभाग को नोंचने से फुर्सत मिले तब न।

इसके भी रुपए 2000 करोड़ डकारने की व्यवस्था है। जिसमें एडीबी ऋण, बीओटी ठेकेदारों से वसूली भी शामिल है। अकेले आजमगढिया आतंकीही रुपए 2000करोड़ डकारेगा। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में सविनि कोई जानकारी नहीं देना चाहता और आरडीसी की साइट पर भी झूठे आंकडे डाल रखे हैं।

कृषि व अन्य गतिविधियां

म.प्र. बजट 10-11

रुपए 290 करोड़ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना- इस योजना के अंतर्गत रुपए 200 करोड़ के वारे-न्यारे होंगे, जिसमें से रुपए 100 करोड़ विभाग के अधिकारी जो क्षेत्रों में बैठे हैं से लेकर संचालक तक और रुपए 100 करोड़ सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, कृषिमंत्री और मुख्यमंत्री के हिस्से में पहुंचेगे रुपए 90करोड़ ही लक्ष्य में पर वास्तविक खर्च होंगे। सब झूठे व्हाउचरों से होगा करिश्मा।

रुपए 61 करोड़ कृषि बीमा- पुराना इतिहास देखें कितने किसानों को बीमें का लाभ मिला या अब रुपए 61 करोड़ में से मिल सकेगा? पूरा कागजी खानापूर्ति होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा।

रुपए 183 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रुपए 33 करोड़ भी इस योजना का वास्तविक लक्ष्य पर खर्च हो तो प्रदेश के किसान भी धन्य हो जाएंगे,बाकी रुपए 150 करोड़ का हश्र.... पाठक समझदार हैं?

नगरीय अधोसंरचना

अ- जवाहरलाल नेहरू शहरी पुर्ननवीनीकरण मिशन के अंतर्गत रुपए 3181 करोड़ मुश्किल से ही होगा।

ब- एकीकृत शहरी व मलिन बस्ती विकास में रुपए 280 करोड़ में से रुपए 100 करोड़ का कार्य रुपए 180 करोड़ भ्रष्टाचार में हजम होंगे।

स- लघु एवं मध्यम नगरीय अधोसंरचना रुपए 762 करोड़ में से रुपए 500करोड़ भ्रष्टाचार में रुपए 262 करोड़ लक्ष्य पर खर्च हो जाएं तो प्रदेश की जनता का अहोभाग्य हैं।

उपरोक्त तीनों योजनाओं में 10-11 में रुपए 520 करोड़ का आवंटन होगा स्वाभाविक है रुपए 300 हजम होंगे, भ्रष्टाचार में रुपए 220 करोड़ भी वास्तविक लक्ष्य पर खर्च नहीं किए जाएंगे।

नगर विकास योजनाओं में रुपए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदौर-भोपाल मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की योजना की जो बात बजट में कही गई है तो पाठक स्वयं सोचें कि इंदौर को 2005-06 में आबंटित रुपए 868 करोड़ का क्या हुआ, शायद वो हजम हो गए पुनः नई योजना लाई जाएगी।

प्रदेश की ग्रामीण बसाहटें, शासकीय कार्यालयों और ग्रामीण शालाभवनों शुद्ध पेयजल योजना पूर्व से ही लागू है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को 10-11 के लिए रुपए 1051 करोड़ का प्रावधान है रुपए 600 करोड़ कागजों पर खर्च होंगे और 551 करोड़ में से लक्ष्य पर रुप 250 करोड़ बाकी सरपंच, विधायकों, इंजीनियरों से लेकर सचिवों, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बंटेगा।

कुल खर्च रु. 51507.31 करोड़ रु. 20000 करोड़ वेतन, भत्तों, शासकीय सेवाओं, रखरखाव, कार्यालयीन व्यवस्थाओं आदि में खर्च हो जाएगा, बाकी रु. 31507.31 करोड़ में से रु. 20000 करोड़ भ्रष्टाचार में हजम, रु. 11501.31 लगभग में से रु. 6000 करोड़ वास्तविक लक्ष्य।

कुल आगमआय रु. 43443.82 करोड़ जो वास्तविक प्राप्त होने वाली आय का मात्र 50% ही है। सबसे बड़ा स्त्रोत विक्रय या वाणिज्यकर से मात्र 50% ही आय प्राप्तह ोती है। 50% से ज्यादा चोरी जिसमें 10 से 15% विभागीय अधिकारी हड़प जाते हैं। इस वर्ष रुपए 8000 करोड़ संभावित हैं, अर्थात इससे ज्यादा चोरी होती है।

आबकारी से भी कुल 40 से 50% ही प्राप्त होता है, बाकी चोरी।

खनिज विभाग से मात्र 15 से 20% ही आय प्राप्त होती है 40% चोरी और 10 से 15% विभागीय निरीक्षक से मंत्री तक डकार जाते हैं।

मुद्रांक व पंजीयन से भी 50 से 60% आय होती है, 5 से 10% पंजीयक कार्यालय में बैठे उपपंजीयक से जिला पंजीयक तक बंदरबांट।

केंद्र से प्राप्त राज्यांश जो आयकर, बिक्रीकर,(केंद्रीय), कस्टम एंड एक्साइज सेवा कर भी वास्तविकता में 30 से 40% ही संग्रहित होता है, 10 से 15% आयकर, कस्टम निरीक्षकों से लेकर आयुक्त और मंत्रीतक भ्रष्टाचार में हजम कर जाते हैं। स्वाभाविक है राज्यांश केंद्र सरकार भी आयोजन में उसी अनुपात में राशि आबंटित करता है।

आयोजन व्यय पर अनुमानित रुपए 21939-12 करोड़ में से रुपए 15000 करोड़ बंदरबांट में और बचा हुआ 693912 करोड़ वास्तविकता में ही खर्च होगा।

आदिवासी उप आयोजन में अनुमानित रुपए 4090.77करोड़ में से रुपए 3500 करोड़ बंदरबांट और भ्रष्टाचार में हजम हो जाएगा। रुपए 590-77 करोड़ भी लक्ष्य पर मुश्किल से खर्च होगा, इतिहास और वर्तमान के सह योजन से भविष्य का परिदृश्य है।

अनुसूचित जातियों पर उपआयोजन

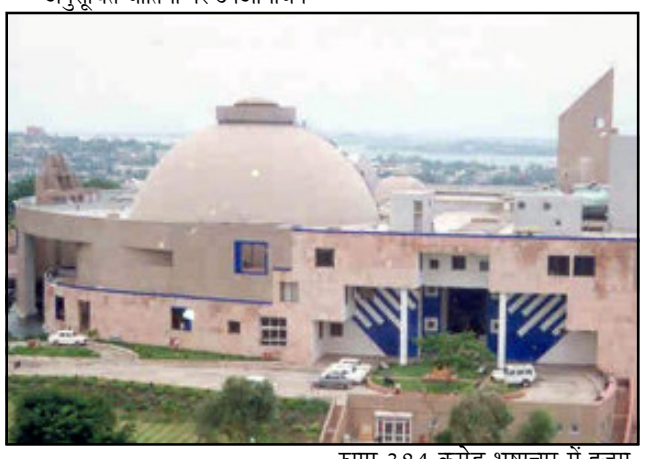

बजट अनुमानित रुपए 2496.85 करोड़ में रुपए 2000 करोड़ बंदर बांट और भ्रष्टाचार में समाप्त होगा, यह सब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से बेकर सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बंटेगा।

उद्योग एवं खनिज साधन

60- उद्योग को बढ़ावा देने में 10-11 में रुपए 233 करोड़ रुपए उद्योग एवं वाणिज्य सचिव, प्र. सचिव, मु. सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर म.प्र. औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कागजी खानापूर्ति, सैर, सपाटे, आयोजन 5 सितारा होटलों की मौजमस्ती में हड़प जाएंगे, उद्योगपति आएंगे मुंह पर हां करेंगे, फिर पलटकर नहीं देखेंगे।

61 शहडोल और अनूपपुर में मिले मिथेनगैस के 36.5 खरब घन मी. गैस भंडार जो मिले हैं। अपने आकाओं अंबानी, टाटा, बिरला या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचकर या गिरवी रखकर रुपए 5-7 हजार करोड़ में सौदा पक्का कर लेंगे, मंत्री, मुख्य सचिव, , मु.या.प्र.सचिव मिलकर बंदरबांट कर लेंगे, जनता वहां की वहीं तरसती रह जाएगी अन्यथा ईमानदारी स उपयोग करने पर जनता से बिना एक पैसा किसी प्रकार का कर वसूले श्रेष्ठ अग्रणी राज्य बनाया जाकर जनता को भरपूर रोजगार देकर सम्पन्न किया जा सकता है।

पर्यटन विकास

58 करोड़ का प्रावधान है पर्यटन विकास पर व्यय के लिए रुपए 8 करोड़ भी 100 से ज्यादा पर्यटन केंद्रों पर नहीं लगेगा,

खेलकूद-रुपए 79 करोड़ आबंटन

यह बजट भी कागजों पर ही खेलकूद कर हजम कर लिया जाता है। इसके रुपए 9 करोड़ भी वास्तविकता में खर्च हो जाएं तो भी 5-10 करोड़ के वितरण की जानकारी के लिए भोपाल में संचालक नेहरू युवा कल्याण और खेलकूद को पत्र दिया था सूचना अधिकार में हरामखोरों ने भ्रष्टाचार के कारण जवाब तक नहीं दिया।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास में रुपए 3685 करोड़ के व्यय का प्रावधान है- जिसमें रुपए 584 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मात्र रुपए 2000 करोड़ ग्रामीणों की मजदूरी में बंटेगा। 40% धन हर प्राक्कलन में सामग्री खरीद के लिए होता है। अर्थात रुपए 384 करोड़ भ्रष्टाचार में हजम, रुपए 475 करोड़ पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि का 90% कार्य कागजों पर होकर ही भ्रष्टाचार में हजम हो जाता है। इंदिरा आवास योजना में रुपए 87 करोड़ में से रुपए 17 करोड़ के भी गरीबों को आवाज मिल जाएं तो बहुत है उनके नाम से सरपंच से लेकर मु.का.अधि. जनपद व जिला पंचायत डकार जाते हैं। समग्र स्वच्छता अभियान में रुपए 53 करोड़ की स्वच्छता कागजों पर ही सम्पन्न हो जाएगी। इंटीग्रेटे डवाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम रुपए 15 करोड़ में पुराने इतिहास के अनुसार 80-90% कागजों पर ही सम्पन्न हुआ है। जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रुपए 100 करोड़ से सारे कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर मु.का. जिला पंचायत की गरीबी ही दूर होती आई है, अभी तक।

म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना रुपए 73 करोड़ से सरपंचों, पंचों और जनपदों, जिला पंचायतों के कर्मियों, अधिकारियों की जीविका चल रही है, ग्रामीण कागजों पर ही है।

43. शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों से लेकर सरपंचों, नगर पालिकाओं, निगमों के शिक्षा के नाम पर भोजन की 10 माह व्यवस्था होती है, इसीलिए ये विद्यार्थियों से लेकर संबंधित भ्रष्टाचार से धन डकारने वालों की भीड़ बड़ी है।

44. राज्यांश रुपए 584 करोड़ के साथ केंद्रीय राशि रुपए 5000 करोड़

म.गा. रा. ग्रा. रो. गारंटी कार्यक्रम में कुल रुपए 5584 करोड़ मिलेंगे, अर्थात भ्रष्टाचारियों को रुपए 3000 करोड़ न्यूनतम डकारने का पूरा लाभ मिलेगा हर जिले को रुपए 110.84 करोड़ साल भर लूटने के लिए औसतन आवंटित होगा।

रुपए 17 करोड़ सिंचाई उपकरण अनुदान किसानों को

म.प्र. कृषि और उद्यानिकी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले इन उपकरणों पर 25%, 33% और 50% का अनुदान पर 25 से 50% अनुदान कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलने पर ही किसानों को मिलता रहा और रहेगा अर्थात रुपए 5 से 8 करोड़ कृषि और उद्यानिकी वाले ही हड़प कर जाएंगे।

रुपए 119 करोड़ वृहत प्रबंधन योजना-पुरानी योजनाओं में खर्च किया गया अधिकांश धन जैसे किसान मेला, प्रदर्शनी आदि का 50% ही वास्तविकता में भी खर्च नहीं किया जाता पर झूठी कागजी खानापूर्ति कर डकारा जाता है। जितना खर्च किया जाता है उससे दुगुना प्रबंधक विभागीय स्वयं डकार जाते हैं। ऐसी योजनाओं प्रदर्शनीयों, मेलों में भाग लेने वालों से पिछले कई मेलों में इंदौर-उज्जैन- धार-देवास, शाजापुर, खरगोन, के साथ पूरे प्रदेश में हुआ।

रुपए 300 करोड़ का बोनस-गेहूं और चावल की खरीद-

यह बोनस किसानों को तब मिलता है जब सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से खरीदें, जबकि पुराने इतिहास में पहले व्यापारी किसान से खरीद लेता है, उन्हीं रसीदों को सरकारी एजेंसियांह अपने खाते में दिखाकर व्यापारी और म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्य, या म.प्र. कृषि विपणन संघ व अन्य आपस में आधा-आधा कर डकार जाते हैं।

रुपए 100 करोड़ ब्याज अनुदान बैंकों को 3% ब्याज दर पर किसानों को कृषि ऋण के नाम पर बैंकों के इतिहास गवाह हैं कि किसानों को राज्य सरकार के अनुदान का फायदा कभी नहीं मिला और जिला अधिकारी, जिलाधीश, कोषालय, कृषि जिला अधिकारियों द्वारा दिया गया धन बैंकों में उच्चंत में डालकर आपस में बंदरबांट कर कुछ किसानों को दिखाकर डकारा गया, वैसे भी प्रदेश के 50 जिलों में रुपए 2 करोड़ प्रति जिला ही मिलेगा। किसानों से केंद्र सरकार का 5% से 12% का अपेक्षित दरों पर व्यंजन ही मिल पाता, किसानों को बैंक अपनी दरों पर ऋण देते हैं किसानों के वास्तविक खर्च लक्ष्य पर रुपए 27 करोड़ ही होगा, बाी 1 अरब रुपए कागजी खानापूर्ति में हजम होंगे जैसा कि पुराने दस्तावेजों से देवास जिले के स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुए हैं। कहानी कहते हैं।

महिला बाल विकास

रुपए 22.01 करोड़ एकीकृत बाल विकास के लिए इस राशि में से रुपए 15 करोड़ शहरीय केंद्रों से लेकर विकास खंडों तक केवल कागजी खानापूर्ति से हजम कर लिए जाएंगे, जैसा कि सूचना के अधिकार में प्राप्त दस्तावेजों से प्राप्त इतिहास रहा है।

रुपए 744.55 करोड़ पोषण कार्यक्रम- आंगनवाड़ी में 50 से 80% फर्जी बच्चों को दिखाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी तक रुपए 600 करोड़ डकारेगें। रुपए 300 करोड़ ऊपर मंत्री, सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तक बंटेगा।

रुपए 302 करोड़ लाडली लक्ष्मी योजना- के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जिला कार्य अधिकारी तक रुपए 50 से करोड़ डकार लिया जाएगा। योजना का लाभ केवल अपनो-अपनों को ही मिलता है।

रुपए 94करोड़ स्कूली छात्राओं को सायकल के लिए- फर्जी खरीदी में रुपए 34 करोड़, रुपए 10 करोड़ का कमीशन में हजम होंगे।

रुपए 28 करोड़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना- इस योजना में रुपए 8 करोड़ तो सरकारी कार्यक्रमों के सम्पन्न करने रुपए 20 करोड़ से ग्रामीण गरीब कन्याओं के विवाह और दान दहेज की व्यवस्था में खर्च होना चाहिए। 50% वास्तविक हो जाए को प्रदेश की शादी योग्य कन्याओं के साथ मुख्यमंत्री और सत्ताधीशों का जीवन भी धन्य हो जाए।

कर्मचारी कल्याण- वैसे तो उपरोक्त बजट भी कर्मचारी कल्याण के ही काम आएगा, पर 10% जो मौका न मिलने के कारण ईमानदार हैं।

रुपए 1017 करोड़-6वें वेतन मान के वेतन पुर्ननिर्धारण की पहली किस्त के जो बकाया के भुगतान के लिए हैं।

पेंशनर्स और कर्मचारियों को 3% अप्रैल 2010 में और 2 % जुलाई 2010

अन्य महत्वपूर्ण मद-

म.प्र. शासन 10-11 बांस वर्ष के रूप में मनाएगा- जनता तैयार रहे अगाड़ू-पिछाड़ू केंद्र व राज्य दोनों ही लट्ठ बरसाएंगे।

5 करोड़ बांस धरती पर और 6 करोड़ जनता के दिल पर रोपेंगे।

रुपए 20करोड़ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के नाम पर श्रम विभाग के अधिकारी मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर बैंक बैलेंस और जेब की सुरक्षा में झूठे व्हाउचरों, कागजी खानापूर्ति में रुपए 15करोड़ तक डकार जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रुपए 777 करोड़- रुपए 500 करोड़ से शा. अधिकारियों से लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की सुरक्षा।

रुपए 683.31 करोड़ का राज्य और रुपए 1200 करोड़ केंद्र का बुंदेल खंड विकास योजना- दोनों ही वोट सुरक्षा के नाम पर हजम करने के काम आएंगे, सागर, जबलपुर संभागों का सूखादार हो जाएगा।

रुपए 55 करोड़ प्रदेश की चेक पोस्ट को कम्प्यूटराइज्ड करने हेतु भूमि अधिग्रहण करने हेतु प्रदेश की 29 चेक पोस्ट में कौन कितना माल वसूल कर रहा है जेब में ये देखने और किसका माल कितना सुरक्षित तरीके से आ-जा रहा है नहीं।

शिक्षा

रुपए 6009 करोड़-प्रदेश के स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों के सिक्षकों तक के वेतन में अधिकांश खर्च होता है, बेशक रुपए 200 से 300 करोड की बंदरबांट होगी।

रुपए 799 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान का राज्यांश- इसमें रुपए 600 करोड़ डकार लिया जाएगा। यह अभियान केवल कागजों पर ही चल रहा है। इसके नाम पर शिक्षामंत्री से लेकर जिला अधिकारी स्तर कर भारी भ्रष्टाचार और लूटखसोट होती है।

रुपए 17 करोड़ गांव की बेटी योजना- इस पर भी लक्ष्य पर वास्तविक खर्च 40 से 60% ही हो पाएगा, विकास खंड शिक्षा **शेष पेज 7 पर**

पीथमपुर में युका की मिक धन के लिए दफन

भोपाल गैस- 25वर्ष बाद भी धीमी मौत की कारक

म.प्र. शासन और प्रदूषण मंडल ने धन डकार इंदौर को दी मौत उपहार

भोपाल। में 2 दिसम्बर 1984 को हुए यूनियन कार्बाइड के हादसे में जहां तत्काल 20,000 से ज्यादा लोगों को कुछ घंटों में ही मौत हो गई थी। उस मिक गैस को इंदौर की औद्योगिक नगरी पीथमपुर के आधे अधूरे बने रेमको और म.प्र. प्रदूषण मंडल के षड्यंत्र भंडारगृह में कुछ तो चोरी-छिपे लाकर दफन कर ही दिया गया है और बाकी बचे को दफन कर म.प्र. की भाजपा सरकार अपने ही भाजपा के ठोस गढ़ की 25 लाख क़ी और पीथमपुर उसके आसपास बसे महू, इंदौर, राऊ को 5 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ ही भारत के रक्षा संस्थान के महत्वपूर्ण गढ़ को भी लंबी बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। यह है भाजपा की महापौर, विधायकों और सांसद को वोट देने का उपहार म.प्र. की इस व्यावसायिक नगरी की जनता को धन्य है भाजपा और उसके षड्यंत्रकारी नेता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाजपा की मूल।

हमारे समयमाया के मुख्य सम्पादक श्री अजमेरा ने 23 जुलाई 04 की जनसभा में जो आशंका व्यक्त की थी वह अक्षरशः यथार्थ में बदल चुकी है। जिसे हमारे पत्र ने लगातार जनता के सामने अपने तीखे और कड़वे तेवरों से जनहित में प्रकाशित किया था, पर शायद ये इस राष्ट्र का दुर्भाग्य और हजारों वर्ष के ऐतिहासिक गुलामों की घोर स्वार्थी नीतियों और मानसिकता है कि यहां तत्काल का लाभ चाहिए कल इनकी और इनकी वाली पीढियों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं होता। सत्ता और प्रशासन के सत्ताधीशों को तत्कालक आता हुआ धन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजाए इसके कि उनकी आने वाली नस्ल क्या सोचेगी, मरेगी औचित्यहीन हैं। जबकि जिस पहाड़ी के ऊपर उसे बनाया गया है उससे बहने वाला बरसाती पानी का नाला चम्बल में और चम्बल इटावा में गंगा में मिल जाती है। अंदाज लगाया जा सकता है कि बर्बादी भारी होगी।

इस बर्बादी का जिम्मेदार प्रदूषण मंडल धार, पीथमपुर का तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक अहिरवार जिसे रेमको इन्वायरों का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में लाखों रुपए की मोटी भेंट मिली थी। प्रमाण पत्र देकर निकल गए। बदले में रेमको इन्वायरों को रुपए 8 करोड़ का अनुदान मिलता था, जबकि उसके भस्मक उसके नक्शे बनाने से लेकर जमीन आवंटन तक में खुलकर भ्रष्टाचार और जालसाजियां हुई थीं। संक्षेप में रुपए 25 करोड़ के इस्टमेंट का नक्शा 60 एकड़ जमीन के आधार पर बनाया गया था, बकि जमीन का आबंटन मात्र 20 एकड़ ही हुआ, अर्थात 33% अनुदान में ही उस कंपनी ने रुपए 6 करोड़ से ज्यादा डकार लिए ते। जो डिजाइन बनाया गया था उसको बाजू में रखकर केवल सही अर्थों में गोडाउन बना दिया गया, जिसे वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबंधक त्रिवेदी धार, पीथमपुर प्रदूषण फैलाओं

मंडल ने स्वीकार कर लिया अर्थात षड्यंत्रों और जालसाजियों का ये भस्मक सारे प्रदूषित कचरे को जलाकर नष्ट करने की अपेक्षा वहां डंप करता जा र हा है औप कचरा देने वालों से मोटी राशि वसूल कर हजम कर रहा है, जबकि त्रिवेदी को उसको नष्ट करने की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण और देखरेख करना चाहिए। यूनियन कार्बाइड की मिक गैस को भोपाल से इस भस्मक में भस्म कर नष्ट करना चाहिए था जो लाकर पटक दिया गया है, बेशक इस लेनदेन में शिवराज और उसके पर्यावरण और आवास के साथ उसके प्रधान सचिव, सचिव, अध्यक्ष, सचिव और क्षेत्रीय प्रबंधक को भी करोड़ों रुपए का कमीशन मिला। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश को भी उपकृत कर वास्तविकता छिपा कर पीथमपुर में दफन करने का आदेश प्राप्त कर लिया गया।

इसके विपरीत इस गैस कांड को गुजरे हुए भले ही 25वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। प्रदूषण पर निगरानी करने वाली दिल्ली की संस्था के अनुसार उस फैक्ट्री के 2 से 4 किमी के वृत्त में उसका जहर अभी भी मिट्टी और पानी में बरकरार है। केंद्रीयप्रदूषण मंडल की गई जांच गहन जांच में पाया गया कि 390 टन विषैला रसायन अभी भी फैक्ट्री के भूमिगत भंडारों में जमा है, जिसमें क्लोरोफार्म और बैंजीन है वहां से बहने वाले वर्षाजल और नालों में मिल रहा है। जबकि पर्यावरण और विज्ञान केंद्र ने यह तथ्य जुटाकर दिए थे कि यह जहर अभी भी पानी में मिल रहा है और पानी में पाया जा रहा है। जिसकी पुष्टि केंद्रीय पर्यावरण और आवास मंत्रालय ने भी की। कई मामलों में पानी के स्त्रोतों जिनमें पेयजल भी शामिल है इस विषैले रसायन के कारण हजारों गुना स्वीकृत सीमा से ज्यादा है जिसमें पारे की मात्रा 7996 कण प्रति दस लाख (पीपीएम) थी जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह सी.0.1 पीपीएम से किसी भी हाल में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस मिलावट के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष एस.पी. गौतम ने भी माना कि पानी में यह मिलावट बहुत ऊंची है। उस वक्त इस मिथाइल आइसोसायनेट से लगभग 20,000 से ज्यादा तत्काल मर गए थे और 5लाख से ज्यादा इस गैस के दुष्यप्रभावों से पीड़ित हुए जो कुछेक लाख लोग अभी भी इसकी पीड़ा भोग रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण मंडल ने गहन जांच के बाद ये भी पाया कि आसपास की ढाई से तीन किमी वृत्त की मिट्टी में मुख्य रूप से आर्सेनिक, पारा, जस्ता, केडमियम जैसी विषैली और घातक धातुएं सामान्य से हजारों गुना ज्यादा है। पर्यावरण और विज्ञान केंद्र की सुनीता नारायण भी इस विषैली मिलावट को स्वीकारा है कि यह मिश्रण अत्याधिक हैं। इन सबके विपरीत म.प्र. सरकार और प्रशासन जानबूझकर उस 290 टन मिक के कचरे को पीथमपुर में बिना नष्ट और भस्म किए दफन करवाने पर तुली है। साथ ही म.प्र. प्रदूषण मंडल का इंदौर, पीथमपुर, धार, उज्जैन, मंडल और भोपाल के मुख्यालय में बैठे धूर्तों, जालसाजों का जमावड़ा यह सिद्ध करने पर तुला है कि 25वर्ष बाद उसका सारा प्रभाव नष्ट हो चुका है और पीथमपुर में दफन करने से कोई परेशानी नहीं आएगी।

भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में आखिर क्यों?

इंदौरी मीडिया झूठन चाटने वाले भांडों की फौज

भाजपा का 17,18,19 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ। आखिर इंदौर में ही क्यों हुआ भाजपा का सम्मेलन? इसके बारे में वल्लभ भवन के गलियारों में 5 फरवरी से ही बहस शुरू हो गई थी।

आखिर सारा आयोजन सन 2005 से मुख्यमंत्री की कतार में खड़े इंदौरी मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर में क्यों किया? इसका स्वाभाविक सा कारण था कि अपना कद राष्ट्रीय नेताओं में स्थापित करना, मुख्यमंत्री के इंतजार में 2005 से खड़े हैं उसकी काबलियत सिद्ध करना ये सब साधारण प्रत्यक्षकरण थे जो हर पाठक अंदाज लगा चुका है।

ओमेक्स सिटी में कार्यक्रम आयोजित कर इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ प्रशासन देने के दावे को स्वयं नोंच कर अपनी भ्रष्ट मानसिकता, पूंजीपतियों, जालसाजों को संरक्षण देने उनस कमाई करने और उनकी कमाई को बढ़ावा देकर, बिखैर दिया है। दूसरा यह भी सिद्ध किया है किग इन सब नेताओं, मंत्रियों, इंजीनियरों,डॉक्टरों अधिकारियों, आई.ए.एस., आईपीएस, आईआफ एस आई और एस.आई.एस. अधिकारियों से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तक उद्योगपतियों, पूंजीपतियों से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तक, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, प्रदेश की ऐसी हजारों कालोनियों में पैसा लगा हुआ है। उसका इस बहाने व्यावसाय संवर्धन कर पैसा निकालने ताकि माल जल्दी बिक सके। लाख कानून अवैध चिल्लाए ये स्वयं वहां सम्मेलन कर उनकी वैधता सिद्ध कर रहे हैं। 25 जनवरी 10 से पूर्व समयमाया ने अपनी साइटों से देश के सामने यह सच्चाई व्यक्त कर दी गई थी। इंदौर के दैनिक समाचार पत्रों ने यह बात छापी भी, मुख्यमंत्री भी चिल्लाए, फिर अपने आप से पूछा किसी ने सुना तो नहीं, अगर सुन भी लिया है छप भी गया है तो सब भूल जाएं, क्योंकि हिस्सा तो मैंने भी हजम किया है, म.प्र. इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार, जालसाजियां, कदम दर कदम होती हैं। तो जमीनों की कीमतों के बाद मकानों की कीमतें भी ज्यादा हो रही हैं। पिछले 50 वर्षों से दूसरा जनता के पास प्रदेश की तुलना में पैसा भी ज्यादा है। बेशक काला धन, उसका विनियोजन भी शीघ्रता से करना आवश्यक होता है। उसके बाद आने-जाने का चक्र चलता रहे तो ठीक अगर पैसा दो नम्बर का रुका और लेन वाले की बदली तो तकलीफें बढ़ जाती है। नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को उसकी वसूली भी करना है, फिर भाजपा के सम्मेलन से बेहतर कौन सा विकलक्प हो सकता था। फिर ओमेक्स की व्यवस्थाएं भी अपने आप सुधर गईं, अब तैयार है प्लेट खरीददार चाहिए।

फिर इन सब कारणों के पीछे छोड़ भी दें तो भी मुख्य कारण होता है मीडिया कैसा है। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों में मीडिया झूठन चाटने वालों का गिरोह है। अर्थात वर्तमान में इंदौरी मीडिया की छवि को नई दुनिया, भास्कर, राज, पत्रिका आदि ने पूंजीपतियों और पावर वालों का भांड हैं ये बड़े से बड़े भ्रष्टों, जालसाजियों को प्रवर्धित करने वालों

सभी अवैध कालोनियां जिनमें मंत्रियों, अधिकारियों का पैसा भी लगा है विक्रय प्रबंधन का हिस्सा

की भांड फोज है जो पावर और पैसे के लिए सिर झुका कर उनके दुष्यकृत्यों, कमीशन खोरी, जालसाजियों के गुणों की प्रशंसक, समीक्षा पढ़ती और बताती है। यही कारण था कि गणकारी ने भी मीडिया को एक तरफ कोसा तो दूसरी तरफ धिक्कारते हुए मीडिया कर क्या लेगा,कहकर सिद्ध कर दिया कि यहां की पत्रकारिता का स्तर क्या है?

इंदौर अपने यौनाचार, स्वच्छंदता की मंडी के रूप में कुख्यात है। 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग फार्मा, प्रबंधन कम्प्यूटर शिक्षा के कालेजों में पढ़ने वाली यौवनाएं पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। स्वागतकर्ता के रूप में आबंटन करने वाली एजेंसी की तरफ जींस- टीशर्ट में बैठाई गई थीं, फिर इंदौर, उज्जैन संभाग की 1200 से ज्यादा पंचायतों की भाजपा की 50% पंच, सरपंचों से लेकर 14 जिलों की नगर पंचायतों, जनपदों की नगर पालिका निगमों की 500 से ज्यादा महिला प्रतिनिधि भी बाहर से स्त्री-पुरुष प्रतिनिधियों के मन बहलाने के सभी प्रकार से ख्याल रखने में सक्षम थी। शहर से 10 किमी दूर थी ओमेक्स सिटी जहां पर सभी प्रकार के भोजन की व्यवस्था थी, फिर यहां वो शाम 7 बजे बकायदा स्त्रीयों के नृत्य और आमोद-प्रमोद की व्यवस्था थी, फिर हर महिला नेत्री और कार्यकर्ता अच्छी तरह जानती है कि आगे बढ़ने के लिए पुरुषों पर राज करने के लिए टिकट हथियाने के लिए यौनाचार से बढ़ा सटिक और घातक आसान हथियार कोई नहीं है जो न केवल सटीक वरन जीवन रहने तक स्थाई असर कारक है। जिससे पुरुष रूपी बच्चा खेलने के लिए हर वक्त बैचेन है। इस सम्मेलन 90% नैत्रियां इसी तैयारी में आईं थीं। जबकि भोपाल में न तो पत्रकार सुनते हैं और नारी नैत्रियों यौनाचार करने से पूर्व और पश्चात अपनी शर्ते और अपनी सूची की इच्छाओं को पूर्ण करने की तैयारी में रहती है, जिससे 5 से 10% मामला इन सबकी सच्चाईयां संबंधों सत्ता से ऊपर गैर कानूनी काम करने की बातें भोपाल में बहुत जल्दी भभकती हैं। पर इंदौर में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी फिर वे सब ही संगठन और स्त्रीयों को संगठनमें लाने का कारण है ताकि हर नेता व नेतड़ी इस में उलझी रह कर बड़े नेताओं की इच्छानुसार काम करे, बेशक इन सबकी चर्चा में जो भोपाल के वल्लभ भवन में चली 25 जनवरी से 15 फरवरी 10 तक उसके ही अंश हैं। अरविंद और टीनू जोशी, आईएएस दम्पत्ति के पास जो साढ़े तीन करोड़ रोकड़ पकड़ा गया वह भी भाजपा सम्मेलन का चंदा था। जो प्रमोटी आईएसएस जानते थे, उन्होंने ही आयकर को खबर की। इससे दोनों काम एक साथ हो गए। एक परीक्षा पास करके आए सीधे पदस्थ आईएएस को उनकी औकात दिखा दी। दूसरी जो चंदा सम्मेलन में देना था वह भी बच गया। चूंकि मामला भाजपा के सम्मेलन से जुड़े चंदे का था इसलिए आयकर वालों को शिकायत मिलने के बाद छापा डालने की अनुमति का काम भी 48घंटे में ही सम्पन्न होकर 4 फरवरी को एक साथ पूरे म.प्र. और छत्तीसगढ़ से ज्यादा छापे मारकर माल भी पकड़ा गया। और सम्मेलन से ठीक पूर्व छापा मारकर भाजपा की सच्चाई को उजागर कर दिया गया।

जनता का धन बाप की जागीर नहीं जो किसी को भी बांटो

रुपए १६५०० करोड़ बैंकों की जालसाजियों के लिए

भारत शासन ने 10-11 के बजट में आखिक बैंकिंग उद्योगों को रुपए 16500 करोड़ क्यों दिए,प्रधानमंत्री गुलाम सरदार मनमोहन सिंग, जालसाज वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी व कांग्रेसी गिरोह के अन्य डकैतों के बाप की जागीर नहीं वो जनता का धन था, एकतरफ तो बाजारों से रुपए 2500 करोड़ का ऋण लिया जा रहा है, जिसजे जनता के करों से वसूल कर चुकाया जाएगा, दूसरी तरफ बैंकिंग उद्योग जिसमें अय्याशों से लेकर प्रबंध संचालक, संचालकों से लेकर सभी अधिकारी, बाबू और चपरासी तक 95% जालसाजों की फौज है, चाहे वो स्टेट बैंक हो या दूसरी 27 राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ,देश की अन्य सभी निजी और सहकारी बैंकें लेकर कापोर्रेट देशी विदेशी बैंक जालसाज, डकैतों के वो अड्डे हैं जो ग्राहकों से सेवा शुल्क के नाम पर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पर उस पर ब्याज, चेक लौटाने पर यहांतक कि चैकों के संग्रहणों से लेकर ऋण देने, अनुदान स्वीकृत करने तक दोनों हाथ अंटशंट शुल्क वसूलने के साथ भी जालसाजियां भी कर रहे हैं। जानबूझकर ऋणों में जालसाजियां और कमीशन खाकर ऋण बांटते हैं। बड़े-बड़े अरबपति के साथ मिलकर ऋणों और अग्रिमों के नाम पर पहले कमीशन खाकर स्वीकृति देते हैं फिर डुबोने के तरीके बताकर सरकार उसे भी माफ करने के लिए बैंकिंग उद्योग को ऊपर से इतनी जालसाजियों के बाद भी रुपए 16500 करोड़ देने का मतलब, उन जालसाजों और उन साजियों पर पर्दा डाल कर उन्हें इन जालसाजियों के लिए प्रोत्साहन देना ही है।

जब रिजर्व बैंक ही जो कि इन बैंकरों का बैंक इन जालसाजियों को प्रोत्साहन दे रहा है तो सरकार में बैठे डकैतों को इन्हें जनता का धन लुटाने की क्या जरूरत। बेशक हय धन प्रणव और मनमोहन व उनकी गैंग ने आगे के रास्ते देकर व्यापारियों, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों जिसमें अम्बानी, टाटा, आईटीसी और अनेकों राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पहले ही वसूल लिया होगा। कमीशन के रूप में **शेष पेज 5 पर**

बीएसएनएल की राष्ट्रव्यापी जालसाजी

देश में ५० पैसे और प्रदेश में रु. १.२० प्र. मि.

सभी दूर संचार कंपनियां सफेदपोश डकैतों को गिरोह

भारत संचार निगम लि. की ओर से घोषणा केंद्र सरकार ने चुनाव होने के पूर्व की थी. यह घोषणा कांग्रेस ने करके देश के वोटरों को लुभाया और सत्ता में पुनः कब्जा किया, उस घोषणा के अनुसार केंद्र ने 50पै. प्रति मिनट की दरें पूरे देश के लिए घोषित करने के उपरांत भी अभी तक पूरा मप्र बीएसएनएल देश के बाहर तो काल दरें 50 पैसे प्रति मिनट वसूलता है, परन्तु यही मप्र वृत्त के अंदर हरामखोर जालसाजों की फौज रु. 1 रु. से 1.20 प्र.मि. की वसूली करती है।

मप्र बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक से लेकर नीचे तक संभाग और जिलास्तरों पर यह लूट वसूली खुलेआम जारी है। जब इस बात के बारे में बीएसएनएल के नेहरू पार्क स्थित कार्यालय में अधिकारी नवीन सिंग से बात की गई तो उस बंदे का कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हम 1 रु. से 2 मिनट दे रहे हैं बीएसएनएल से बीएसएनएल पर, प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर, अन्य कंपनियों पर ये हरामखोर प्रति मिनट रु. 1 और रु. 1.20 पैसे वसूलते हैं। क्षेत्रीय और म.प्र. व छत्तीसगढ़ में, यह लूट पिछले जनवरी 09 से अभी तक पूरे मप्र व छत्तीसगड़ में की जा रही है। बीएसएनएल भी बेईमानी न केवल लैंडलाइन वरन मोबाइल सेवा की काल दरों में करने के अतिरिक्त ये हरामखोर भी कॉलर ट्यून, मोबाइल टोन के नाम पर एक नं. पर एक ही महीने में 10-15 बार तक काट लेते हैं। इसकी शिकायत इंदौर संभाग के 8 जिलों के महाप्रबंधक पीयूष खरे से भी की गई थी कि 94259-25569 पर रु. 12/- की वसूली के 15-20 एसएमएस आए और धन काट लिया गया, परन्तु सारे हरामखोर है तो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे है, कोई ध्यान नहीं दिया गया।

पूरे प्रदेश के बीएसएनएल के 40 लाख से ज्यादा लैंडलाइन उपभोक्ता से रु. 1 व रु. 1.20 प्रति मिनट के हिसाब से रु. 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध वसूली ये हरामखोर मप्र और छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक पिछले सवा साल से कर रहे हैं। इनकी इस हरामखोरी की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कई बार की जा चुकी है। ये डॉट के अधिकारी अपने लूट, वसूली और भ्रष्टाचार में कभी न आए चाहे पूरा बीएसएनएल बंद हो जाये, की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं, जबकि बीएसएनएल में चल रही भ्रष्टाचार पूर्ण करतूतों से दिनोदिन ने केवल लैंडलाइन वरन मोबाइल उपभोक्ता भी कट व घट रहे हैं। जबकि निगम देश का सबसे पुराना व सबसे बड़ी व विशाल संरचना से युक्त है। इसके विपरीत भ्रष्टाचार से वसूली और दूसरी सेल फोन कं. को फायदा पहुंचाने, अपने ग्राहकों को कम तरंग छोड़ते हैं। यह सच है कि इस काम के लिए एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस से हर महीने इन डॉट के अधिकारियों को महीना मिलता है इसलिए डॉट के ये इंजीनियर बीएसएनएल के ग्राहकों से अनाप-शनाप, मोबालि सेवा में कॉलर टोन, रिंग टोन व अन्य सेवाओं के नाम पर भारी अवैध कटौती करते हैं। साथ ही यही हॉल ब्राडबैंड सेवाओं में भी डाउनलोड के नाम पर भारी वसूली की जा रही है। इंदौर में ही 20/2/10 से इंडस्ट्री हाउस के पास केबल कट जाने से लगभग 5000 से ज्यादा उपभोक्ता 26/2/10 तक परेशान होते रहे सबके ब्राडबैंड बंद पड़े रहे।

प्रदेश में हर जिले में और प्रदेशस्तर दूरभाष उपभोक्ता समितियों के सदस्य और पदाधिकारी भी नकारा और निकम्मों की फौज है, जो करती धरती तो धैलेभर का काम भी नहीं करती है। बस सुख सुविधाएं मिलती रहे उन शूकरों का जनता के साथ निगम की लूट और वसूली से उन्हें क्या मतलब है। मप्र, छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं का कॉल सेंटर भी बीएसएनएल के कर्ताखर्ता पूना के ठेके पर चला रहे हैं। पूना के कॉल सेंटरों की श्वानों की फौज को न तो हिन्दी ढंग से आती है न इंग्लिश, शिकायत 24365 नं. एक तो उठता नहीं 10-25 बार कॉल लगाने पर उठा भी लेंगे तो न काम के लिए हाकर देंगे, परन्तु करते-धरते ये भी कुछ नहीं। टाटा, रिलायंस,एयरटेल सभी अपना अपनी लैंडलाइनों पर 50 पै. प्रति मिनट दे रहे हैं, परन्तु जनवरी 09 की घोषणा में डॉट के ये शूकरों की फौज अभी भी रु. 1 व रु. 1.20 पैसे प्रति काल वसूल करके पूरा बीएसएनएल को बंद करवाने के लिए तो तैयार है, पर सुधरने को तैयार नहीं।

रुपए १६५००... पेज वार का शेष

जनता से लूट, डकैतों और जालसाजों को लूट की पूरी छूट

रुपए 16500 करोड़ देकर रुपए 20000 करोड़ की वसूली नगद या अन्य सम्पत्तियों जिसमें अंधधारिता से लेकर अन्य अनेकों किस्म के लाभ शामिल है प्राप्त कर लेंगे या फिर लिए होंगे।

आखिर सत्ता में बैठे मुखैरे श्वान, मंत्रियों से लेकर असली सत्ता के मालिक इंडियन एव्यूसिंग सर्विसेज के अधिकारियों से आखिर ये पूछताछ कौन करेगा कि जनता का ये धन तुम्हारे बाप की जागीर तो नहीं जो किसी को भी लुटा दिया जाए। भारत का भ्रष्ट मीडिया न केवल शुद्ध भांडों की फौज है जो पैसे और पावर क स्तुतितरक उनका महिमामंडल करता है। दूसरा मीडिया में कितने पढ़े-लिखे लोग हैं जो लेखा, इंजीनियरिंग, विज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र या अन्य विषयों के न तो विशेषज्ञ हैं न ही ज्ञामन पिपासु धैर्यपूर्वक किसी की सत्यता का अध्ययन करना और भविष्य निर्धारित करने जैसी बातों से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं, देश के बड़े-बड़े मीडिया हाऊसों में कितने पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सूचना के अधिखार का उपयोग कियाहो, और जानकारियां व दस्तावेज निकालकर अध्ययन कर सरकार को आईना दिखाते हुए सच्चाई जनता के सामने रखी हो। शायद 1% भी नहीं, उन्हें क्या मतलब है सरकार रुपए 16500 करोड़ बैंकिंग को दे या देश के बड़े-बड़े जालसाज उद्योगपतियों, रिलायंस, टाटा, महिन्द्रा जैसी देशी व अन्य बहुराष्ट्रीय कं. को मंदी की आड़ लेकर जनताको लूटकर हजारोंक रोड़ रुपए आर्थिक मंदी का बहाना बनाकर उनको बांट दें। पूंजीपति, उद्योगपति, एकतरफ जनताको लूटकर व जालसाजियों, से लगाभ कमाएं अपनी लाखों करोड़ की सम्पत्तियां इकट्ठी करें इसके साथ ही सरकारी श्वानों क धन बांटकर वहां से भी पैसा नोंच ले या पैकेज वसूली करें। यदि आर्थिक मंदी है तो लाभ कमाया था तो घाटा भी उठाओ, यदि लाखों करोड़ की सम्पत्ति 2-4 हजार करोड़ करम भ हो गए तो ये शूकर अनिल, मुकेश, टाटा,मित्तल बजाज, मोदी बिरला, डालमियां, भूखे तो नहीं मर जाएंगे। किसी सांसद की औकात है जो संसद में बैठी कांग्रेसी सत्ता के शूकरों से पूछे कि जनता से पेट्रोल-डीजल पर 68% टेक्स वसूल कर महंगाई खाकर ये जालसाज बैंकरों उद्योगपतिय पर हजारों करोड़ क्यों यार किससे पूछ कर लुटाया जा रहा है।

प्र.ग्रा.स.यो. की २९००० किमी सड़कों का रखरखाव कौन करेगा?

मप्र लो.नि.वि. को बंद करने की साजिश

५४१६ किमी राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें छोन, १५ संभाग रा.रा. बंद करने के आदेश

भोपाल। राजधानी के प्रशासन में बैठे गिद्धों इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों को नोचखसोंट और सफेदपोश डकैती का एक साधारण सच 4-5 फरवरी को हरामखोर भ्रष्ट आईएएस जोड़ा अरविंद और टीनू जोशी पर पड़े आयकर छापे ने बयान कर दिया। समय माया अपने अभ्युदय से इन हरामखोर गिद्धों की सफेदपोश डकैतियों पर लगातार सच को प्रकाशित करता रहा है। परन्तु सच 10 वर्षों के बाद अरविंद और टीनू जोशी के रूप में वास्तविकता में सामने आया।

अकेले मप्र में बैठे लगभग 400 से ज्यादा सभी आईएएस अधिकारियों के पास अरबों रु. लेकर हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति इसी प्रकार डकैती जनता के धन पर डकैती डालकर बनाई गई है। टीनू अरविंद जोशी की जो 3 करोड़ रु. की नगदी रु. 500 करोड़ की बेनामी कारोबार सामने आया है। उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति भी इस हरामखोर जोड़े के पास पूरे देश से लेकर विदेशों और स्विस बैंकों में बिखरी पड़ी होगी।

ये भ्रष्ट शूकरों की फौज अपनी लूट के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करने और इन मूर्ख मंत्रियों और मुख्यमंत्री को नचाने में सक्षम होती है। वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी दानव हो या वर्तमान का शिवराज और सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की इन सबकी औकात ही शतरंज की बिसात पर मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं होती; ये सारे श्वान आईएएस उन्हें अपने तरीके से नचाते और हांकते रहते हैं। वैसे भी सारे चुने हुए प्रतिनिधि इनके पाले हुए श्वानों से ज्यादा कुछ नहीं होते। ये आईएएस 30 से 40वर्ष सत्ता भोगते हैं। और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। नोंचते खसोटते रहकरअपनी अय्याशी और मौजमस्ती करते जिंदगी गुजारते हैं। दिग्गी दानव के पंज प्यारों में इकबाल बैस, सुधिरंजन जैसे गिद्ध थे तो शिव की राक्षस मंडली के पंज प्यारो में इकबाल बैस अभी भी है, सुलेमान, अनुराग जैन, मनोज श्रीवास्तव ये वही मनोज श्रीवास्तव हैं जिसने इंदौर में भारी भ्रष्टाचार किया और अब मुख्यमंत्री का चहेता बन पूरे प्रदेश के बड़े-बड़े दैनिक भास्कर,नई दुनिया जैसों को धन बांटकर सभी आई.ए.एस. के भ्रष्टाचार को ढांके रखता है। जबकि 6 जन. 10 को यह बंदा इंदौर के बड़े प्रकाशन के भोपाल प्रतिनिधि की पत्नी को अपनी सेविका बनाकर ले गया था और लौटते समय प्रथम श्रेणी एसी में अपनी मर्दानगी की शोभा बढ़ाते हुए डिब्बे के अन्य यात्रियों के सामने खुले में अश्लीलता फैलानी शुरू कर दी थी इससे सामने की सीटों पर बैठे यात्रियों ने रोकातो साहब अपनी बीवी बताने लगे तो भी लोगों ने समझाया पर न मानने पर मारापीटी कर दी गई थी, जिसकी क्लिपिंग भी कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर निकाली है। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि ये धूर्त गिद्धों की फौज किस हद तक जनधन को नोंचते हुए अय्याशी और मौजमस्ती में डूबी रहती है। वर्षों एकपद पर जमे रहकर अरबों रुपए बटोरती रहती है हर वर्ष।

म.प्र. मु.मं. की राक्षस मंडली में ऐसे आईएएस गिद्धों में एक गिद्ध है सुलेमान यह भी लगभग 5 हजार से 3 हजार करोड़ का मालिक है। पिछले 8 वर्षों से म.प्र. सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक बना बैठा है और अपनी नोच खसोट के चलते इस शूकर ने म.प्र. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग के 15 संभागों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं जो 31 मार्च 10 से बंद हो जाएंगे। उसके अरबों की धन सम्पत्ति को ये बंदर बांट करेगा और उसके पिछलग्गू मंत्री नागोद और मुख्यमंत्री शिवराज को कुछ टुकड़े डालकर टुकड़खोरों के मुंह बंद कर देगा। दूसरे कदम में ये हरामखोर मुख्यालय स्तर पर अपना कमीशन नोंचने और सीधी वसूली के लिए प्रदेश के दस मुख्य अभियंता कार्यालय बंद कर मुख्यालय पर ही दस अलग-अलग विबागों के मुख्य अभियंताओं को बैठा चुका है। ये केंद्रीय सड़क निधि जिसमें रुपए 1000 करोड़ का वार्षिक धन केंद्र सरकार से मिलता है मंडी निधि जिसमें रुपए 800 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सड़कों के रखरखाव और उन्नयन के लिए मिलता है। का भी एक मुख्य अभियंता होगा, रुपए 500 करोड़ से ज्यादा का धन राज्य का, डिजायन स्थापना, सेतु, ई एंड एम। इस प्रकार ये सारे क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय समाप्त करने की है पूरी तैयारी है। 31-3-10 से इसके पीछे इस शूकर का मूल उद्देश्य है कि क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता बैठेंगे तो सारे संभागों के जिलों से 8-9 जिलों में कार्यों के लगने वाली निविदाओं का धन भी इसेही सीधा मिले और अपनी मन पसंद के ठेकेदारों को काम देकर उल्टा सीधा काम करवा कर 20 से 40% सीधा डकार सके। अभी कार्यपालन अभियंता के ऊपर वृत्तों में बैठे अधीक्षण यंत्री और अधीक्षण यंत्रीयों के ऊपर आंचलिक स्तर पर बैठे मुख्य अभियंता का नियंत्रण होता है फिर मुख्य अभियंता पूरे अंचल के सभी कार्यों कूी देखरेख, धन वितरण, डिजाइन, निविदा में अंचल के स्थापना, वेतन पेंशन आदि के कार्यों को अपने स्तर पर ही निपटा लेते हैं। इससे अधीक्षण यंत्रीयों कार्यपालन यंत्री को उनके कार्यालयों को सीधे भोपाल नहीं भागना पड़ता और निर्देश प्राप्त नहीं करने होते। इससे सुलेमान को काफी तकलीफ है अभी तक सुलेमान के पास औसतन रुपए 300 करोड़ से 1000 करोड़ की वार्षिक वसूली हो रही है, उससे इस हरामखोर को आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है। ये प्रदेश की सड़कों पर सीआरएफ, मंडी राज्यनिधि, नाबार्ड, एडीबी से ही सीधे रुपए 50 0 से 1000 करोड़ और बीओटी सड़कों के ठेकों में रुपए 1000 करोड़ सीधे डकारना चाहता है। केंद्र सरकार की स्पष्ट घोषणा कि 4 लेन से कम पर टोल टेक्स न वसूला जाए प्रदेश की 29 बीओटी सड़कों में मात्र 3-4 सड़क ही फोर लेन हैं। बाकी इंदौर-इच्छापुर 2 लेन ही है ऐसी मात्र 8-10 सड़कें ही हैं बाकी सब दूर दराज के क्षेत्रों में 4 मी से 5 साढ़े पांच मी ही चौड़ी हैं। अर्थात सिंगल लेन है जबकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग की थी जिसमें उज्जैन, झालावाड़ भी साड़े पांच से 7 मी. ही है, जबकि टू लेन सड़क भी साढ़े 9 मी. और 5-5 की दोनों और पट्टियां होनी चाहिए। जबकि इन दोनों साइड की **शेष पेज 7 पर**

उज्जैन-इंदौर ४लेन भ्रष्टाचार और दुर्घटनाओं का अंबार

उज्जैन-इंदौर रोड 4 लेन बनाने के लिए जिस वराह कंस्ट्रक्शन जोधपुर वाले ठेकेदार को दिया गया है, वह उसके आदमी आर.पी सिंग और के.पी. सिंग म.प्र. सड़क किास निगम उज्जैन के क्षे.प्र. आर.के. वैध को दिया गया है। जिसका प्रबंधक बैरागी इन दोनों को लाख रुपए महीना का टुकड़ा डालकर ये वराहों की फौज उन्हें अपने जेब में लेकर घूमती है। इसलिए ठेकेदार की फौज क्या कैसे कर रही है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं, जबकि ठेकेदार बनी बनाई सड़क पहले खोदी और कई किमी तक कच्ची सड़क जिस पर गिट्टी आधा और 1 इंच की बिछा दी गई है जो पिछले महाने भर से पड़ी है। उस 100मी. जो गिरधारी मंदिर परिसर के आगे है उज्जैन से लगभग 10 किमी पर, सांवेर से पहले और सांवेर के बाद भी इन शूकरों की फौज कच्ची सड़क जिस पर धूल उड़ती है पुरानी सड़क तो खत्म कर बना दी है और नई अभी पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जान खतरे में रहती है। दो पहिया वाहन चालकों की क्षेत्रीय लोगों के अनुसार हर दिन 10-20 दो पहिया वाहन चलाक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में जब क्षे.प्र. आर.के. बैध से बात की गई तो कहना था कि मैं दिखवाता हूं जबके वराह के.के. पी. सिंग से बात की गई तो वराहों का ये सरदार बोलता है होता रहता है। जिलाधीश इंदौर, उज्जैन को भी कहा गया और पत्र मु.मं., मुख्य सचिव को भी भेजा गया परंतु शुकरों की रिश्वत की गंदगी चाटकर सब ही शूकर बन शूकर ठेकेदार के सामने नतमस्तक हैं।

सड़क औसतन 4 से 5 फीट ऊंची करके बनाई जा रही है, जिसमें प्रति कि.मी. रुपए 1 करोड़ की रायल्टी भी ये वराह शूकर इंदौर-उज्जैन जिले में जमा नहीं कर रहे हैं। अर्थात हर जगह ठेकेदार की शूकरीय प्रवृत्ति का ही बोलबाला है। स्वाभाविक है वाहन चालक पिस रहे हैं। दुर्घटनाओं के शिकार होकर अरविन्दों की कमाई करवा रहे हैं। इस सड़क में भी सांवेर,पंथपिपलाई और धरमपुरी को गांव के बीच से निकली सड़क को बाईपास कर करोड़ों रुपए को एक तरफ मुआवजा डकार लिया, दूसरी तरफ उन जमीनों की कीमत बढ़ाने और सड़क किनारे लाने के लिए भी करोड़ों में लेनदेन के समाचार गांव के लोगों से मिले हैं।

वैसे भी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी सुलेमान जो इस सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक है पूरे प्रदेश में बीओटी की सड़कों इस तरीके से चारों तरफ से अरबों रुपए लूट चुका है और ठेकेदारों को चाहे वो वराह, पार्थ, एमएसके देवास भोपाल कारीडोर हो, वाहन चालकों को लूटने के लिए छोड़ दिया है। प्रदेश में एन.एच.ए. आई. ने भी फोर लेन सड़कें बनाई हैं, परंतु वर्तमान बने व चलती सड़क को तब ही तोड़ा और छेड़छाड़ की जब नया बनाकर यातायात के लिए खोला। आजमगढ़िया आतंकवादी सुलेमान तो सड़कों पर लूट का आतंक तो मचा ही रहा है कुछ लाशें न बिछे दुर्घटना में 100-200 न मरें तो कैसा आतंकवादी।

हर विद्युत कं. में बैठा प्र.सं. डकारता है रु. 300 से 400 करोड़ हर वर्ष

उपभोक्ताओं से बजट से भारी लूट फिर भी प्रदेश में अंधेरा

01-02 में 2935 मेवा से 09-10 में बढ़कर 6057 मेवा हो गई तो कटौती क्यों?

भोपाल। म.प्र. के बजट सत्र में म.प्र. के वि.मंत्री राघवजी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमेंकहा गया है कि म.प्र. 2001-02 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2935 मेगावाट थी जो वर्ष 09-10 में बढ़कर 6081 मेगावाट हो गई है तो भी गांवों में मात्र 4 घंटे तहसील मुख्यालयों पर 12 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 16 घंटे और संभागीय मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली ही मिल रही है। मात्र जबलपुर और भोपाल में 22 से 24 घंटे बिजली मिलता है।

प्रदेश के 8 ताप विद्युत गृहों से 2857 मेगावाट से लगभग 2500 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए जिसमें प्रारंभिक लागत मात्र 20 से 30 पै. प्रति यूनिट की बिजली रुपए 61 से लेकर 12 प्रति यूनिट पर बेचने के बाद भी घाटा, 15 वर्षों से लगातार हर वर्ष बिजली की कीमतों में बेहताशा वृद्धि के बाद में बिजली कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। प्रदेश की 10 जल विद्युत उत्पादन इकाइयों में 917 मे.वाट बिजली प्रदेश के वेतन और संयंत्र के रखरखाव के बाद 15 से 18 पै. प्रति यूनिट आती है और वितरण के खर्च मिला कर 45 से 48पै. प्रतियूनिट होती है।

इसमें इंदिरा सागर के 125 गुणा 8 = 1000 मे.वा. ओंकारेश्वर के 520 मेगावाट और सरदार सरोवर के 54 मे.वाट शामिल नहीं है। जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के हैं और उसमें 60% हिस्सेदारी म.प्र. की है। 40% उत्पादन को भी म.प्र. शासन चाहे तो खरीद सकता है। पर ये हरामखोर वो सस्ती बिजली नहीं खरीदते जिस पर इनका अधिकार है। इसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अपने हिस्से की बिजली भी नहीं खरीदते हैं और अपने यहां बनी उत्पादित विद्युत को बाहर बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके विपरीत यहां जान बूझकर बिना निविदा बुलाए रुपए 1968 करोड़ की बिजली खरीदी गई।

स्वाभाविक था रुपए 1,125 प्रति यूनिट की बिजली रुपए 2.40 पैसे से 3 रुपए के बीट मोटा कमीशन खाकर ही खरीदी गई, वितरण के नाम पर भी जालसाजों, बड़े उद्योगपतियों को 24घंटे निर्बाध बिजली पूरे म.प्र. के उद्योगों को मिल रही है। ये सभी 3 वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक वितरण कंपनियों में बैठकर बड़े बकायादारों को करोड़ों रुपए की बिजली बेचकर उनसे मोटा कमीशन डकार रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली की कीमतें हर वर्ष बढ़ाकर उस होने वाले घाटे को तो दिखा रहे हैं। जबकि रखरखाव, लाइनों, ट्रांसफार्मरों के सुधार के नाम पर भी करोड़ों के खर्च दिखाकर भी भारी हेराफेरी भी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि न केवल घरेलू और व्यावसायिक छोटे उपभोक्ताओं से कई गुना लाभ कमा कर अनाप-शनाप बिलों की वसूली 60% मीटर तेज करके लगाए गए इलेक्ट्रानिक मीटरों से की जारही है। इसके बाद भी घाटे ही घाटे दिखाए जारहे हैं जबकि वितरण लाइनों के उप वितरण केंद्र के खम्भों की वर्षों से पुताई नहीं की जा रही है और उस पर जंग लगे कमजोर हो रहे हैं।

वितरण कंपनी में बैठा हर प्रबंध संचालक बिलों के माफ करने का कांट-छांट करने में ही अनुमानतः रुपए 100 करोड़ से ज्यादा, रखरखाव में भी लगभग रुपए 100 करोड़ और खरीदी में भी मान दंडों को दरकिनार कर रुपए 100 करोड़ से ज्यादा डकार रहे हैं। साथ ये हरामखोर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी शूकर जहां-जहां बैठते हैं बर्बादी और... के नए आयाम स्थापित करते हैं, सभी निगमों, निकायों को अपनी बपौती समझकर इंदौर म.प्र. प.वि.वि. कं. लि. के प्रसं. राघवेंद्र को ही देखें इस श्वान ने पोलोग्राउंड का मेन गेट ही बंद करवा दिया, क्योंकि वहां इसे निवास हेतु बंगला मिला हुआ है। सारी कं. जैसे राघवेंद्र की बपौती हो, यही हाल अन्य 3 विद्युत वितरण कंपनी के भी हैं। विद्युत उत्पादक कं. के प्र.सं. ताप विद्युत गृहों में लगने वाले कोयले का रोना रोते हैं हरामखोर देशी कं. वेस्टर्न कोल फील्ड सदर्न व अन्य कंपनी के करोड़ों रुपए के उधारी बिल तो चुकाते नहीं वरन मोटा कमीशन डकारने के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं, जबकि आयात किए जाने वाले कोयले में भी 70-80% तक कार्बन की मात्रा भी नहीं पाई जाती। ताप और जल विद्युत गृहों में लगने वाली नियमित सामग्री में भी अरबों रुपए का खेल होता है।

उसमें भी वहां बैठा आईएएस हर वर्ष रुपए 100 से 200 करोड़ डकार जाता है।

यही हाल विद्युत संप्रेषण कं. के एमडी का भी है। वो भी रखरखाव और संप्रेषण हानि के नाम पर हर महीने करोड़ों रुपए का खेल करता है जो कि जनता के खाते में वसूली के नाम और हानियां दिखाकर हजम कर लिया जाता है।

वर्तमान बजट में भी रुपए 3220 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आखिर क्यों? जब विध्युत मंडल लाभ में चल रहा था तो किसी को हजम नहीं हो रहा था। उसकी बांटकर 5 कंप. बना दी गई ताकि लूटपाट और सफेदपोश डकैती का पूरा मौका मिले मंत्रीयों जो कि पूरी टुकड़खोरों की फौज होती है उन्हें तो ये हरामखोर अपने अंगना बंधे श्वानों की तरह पालते हैं जब भी कोई घोटाला, भ्रष्टाचार की बात उठे तो उन्हें भौंकने के लिए छोड़ दें। वैसे भी मुख्यमंत्री निवास मे जितने भी एल्सेशियन श्वानों की निकम्मी और भ्रष्ट फौज बैठी है उसका एक ही काम है कि कैसे कहां से पैसे नोंचना चाहे वो शिव प्रिय नंदी इकबाल सिंह बैस प्रधान सचिव हो या अनुराग जैन, एस.के. मिश्रा, सरबजीतसिंह, विवेक अग्रवाल, राजीव दुबे, जे.सी. भट्ट अशोक जनवदे, अजीत श्रीवास्तव, सुधीर कोचर जैसे सारे म.प्र. के छंटे छटाए इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों का काम केवल नोंचखसोट की सफेदपोश नीति का निर्धारण करना ही है। आखिर इन सब हरामखोरों को भी तो टुकड़े चाहिए, इनकी बला से पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहे जनता चीखती चिल्लाती रहे।

जानबूझकर यदि शूकरों की फौज अंधेरा नहीं करेगी तो कीमतें बढ़ाने का कौन सा बहाना मिलेगा, दूसरे रिलायंस, टाटा, जिंदल व अन्य कंपनियों से कैसे मोटा कमीशन डकार कर बिजली बिना निविदा बुलाए खरीदेंगे। बिजली खरीदी में ही रुपए 1000 करोड़ से ज्यादा की कमीशन खोरी हर वर्ष जो की जा रही है। भार जनता के आम लोगों को नोंचकर वसूला जा रहा है। फिर जब तक जमुनादेवी जैसी बिना पढ़ी-लिखी विपक्ष की नेता होगी क्या तूफान खड़े करेगी, क्या प्रश्न पूछेगी जो उन्हें उनके ईर्द-गिर्द रहने वाले तोते की तरह पढ़ा कर भेजेंगे। वहां भी ख़ुलकर सौदेबाजी होती है। समय पूर्व हर सत्र बंद करने से लेकर प्रश्न पूछने और न पूछने में अनेकों जनहित के प्रश्न भेजे जाते हैं। जिनका पता भी नहीं चलता तो फिर बिजली की कमी जानबूझकर पैदा करना, अंटशंट वसूली करना, बकाया जो करोड़ों के देनदार हैं ले-देकर छोड़ना खरीदी में चारों तरफ लूट-पाट, फिर भी छोटी मोटी औपचारिकताएं निभाकर सत्र समाप्त कर दिया जाता है। इन कंपनी के हरामखोरों के सूचना के अधिकार में पत्र दिए तो इंदौर की ही म.प्र. क्षेत्रीय पश्चिम विद्युत बिल कं. लि. ने हर वक्त पुरानी तारीखों में समय के बाद जवाब भेजें। जब वहां बैठे भाड़े के ठेके पर सेवानिवृत्त अधिकारियों से बातचीत की तो मक्कारों की फौज हर हथकंडे अपनाने पर उतर आई। जिसमें गुर्राने, डराने, धमकाने से लेकर सूचना आयोग में द्वितीय अपील लगाने पर वकीलों को लेकर पहुंच गई इन शूकरों की चालबाजियां देखिए कि रुपए 10-20 हजार खर्च करके वकीलों को तो खड़ा कर सकती है, परंतु समय पर पत्रोत्तर अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने और मामला उलझाने के लिए नहीं दे सकती, आखिर वकीलों की फीस दी तो जनता से वसूली के आधार पर ही।

इन कंपनियों में फाल्ट सुधारने से लेकर फाल्ट अटैंड करने, बिलों की वसूली जैसे बहुत सारे कार्यों को उन शूकरों ने सहकारी समितियों, भास्कर जैसों का मुंह बंद करने के लिए ठेकेर पर दे दिए, ताकि तुम भी लूटो हमें भी लूटने दो, जनता, उपभोक्ता को चीखने चिल्लाने दो जितना चीखेगी चिल्लाएगी उतनी कमाई में वसूली और भ्रष्टाचार में सुविधा होगी।

खाद्य व औष. व ननि निरीक्षक वसूली कर सोते हैं

हर दिन ६ लाख ली. दूध नकली बिकता है इंदौर में

हजार से ज्यादा गरीब बस्तियों में वर्षों से चल रहा कारोबार

इंदौर। पिछले 6-7 वर्षों में ही रुपए 12 प्रति ली. का दूध रुपए 28-30/- प्रति ली. हो गया, जबकि वास्तविक दूध का उत्पादन दुधारू पशुओं की दिन प्रतिदिन होती गुणात्मक और संख्यात्मक सभी के चलते दूध उत्पादन पिछले 6-7 वर्षों में ही गिरकर 60% हो गया। इंदौर शहर की 35 लाख की आबादीको प्रतिदिन 12 से 15 लाख लीटर दूध की आवश्यकता मात्र दूध, चाय, काफी पीने के लिए ही होती है। इसके विपरीत दूध मात्र 6 से 7 लीटर में मुश्किल से उपलब्ध होता है। दूध जो गांवों से टंकियों में आता है जो कि सायकल वाले मोटर सायकलों, स्कूटरों से लेकर छोटे और बड़े ट्रकों में भी इंदौर में सभी रास्तों से आ रहा है, चाहे वो धार रोड से, देवास रोड से, उज्जैन, नेमावर, हातोद, सनावद रोड से और चारोंत रफ कच्चे-पक्के रास्तों से जुड़े 400 गांवों से भी दूध आरहा है। दूध जो इंदौर दुग्ध संघ और अमूल का गुजरात से जो दूध आता है दोनों मिलाकर भी 5 लाख ली. दूध उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि चारों तरफ यदि अकेले इंदौर जिले मेंही देखें तो कुल दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है, मात्र 8 से 9 लाख भी मुश्किल से होगी, जिसमें से मात्र 40% दुधारू पशु गाय और भैंस दूध देती है। अर्थात अधिकतम 4 लाख पशु जो अधिकतम औसतन 3 ली. से ज्यादा गायें और औसतन 5 ली. से ज्यादा भैंस दूध नहीं देती है, तो 5 से 7 लीटर दूध कहां से बरस रहा है। स्वाभाविक है कि नकली दूध कम से कम 5 लाख लीटर इंदौर शहर में प्रतिदिन बेचा जा रहा है।

यदि दूध के सीधे उपयोग, चाय, कॉफी की ही बात करें तो अकेले इंदौर की कुल आबादी 30 लाख के हिसाब से आधा लीटर औसतन से 15 लाख ली. और आइस्क्रीम, मिल्क शेक, मिठाइयां जो दूध से बनी बाजार में बिकती है, त्यौहारों को छोड़ भी दें तो 3 लाख ली. दूध की खपत और बढ जाती है अर्थात 18 लाख लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। नवजात शिशुओं से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को औसतन 1 ली. दूध की आवश्यकता भी शामिल है। गंदी बस्तियों में दूध पीने वाले बच्चों में देखा गया कि डेढ़ से दो वर्ष के बच्चे जो इस दूध की कमी लगातार 30-40 वर्षों से चल रही है, 70-80 के दशक में सोयाबीन से बना दूध विकल्प के रूप में बाजार में आया था, पोष्टिक भी था और सस्ता भी, सोया मिल्क पुनः बनाया जाना चाहिए, पूरे देश में 20 करोड़ ली. हर दिन खपत संभावित है। अकेले अंदौर में 8 लाख लीटर दूध हर दिन चाहिए, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार जो दिनों दिन बढ़ेगी, क्योंकि दुधारू पशु कम होने के साथ दूधारू पशु पालना भारी परेशानी और महंगा भी है।

इस नकली दूध के सेवन से न केवल दुबले पतले वरन दो वर्ष के कई बच्चे ढंग से खड़े होकर चल नहीं पा रहे हैं।

इंदौर में दूध के सांची और अमूल भाव बढ़ते हैं तो ये गांवों से लाकर नकली दूध बेचने वाले भी दूध की शुद्धता की बात करते नहीं उल्टे ही दूध की कीमत 26 से 30 के बीच बेच रहे हैं। इस संबंध में क्या पशु चिकित्सा विभाग से बात की गई और कार्य प्रणाली देखी गई तो मालूम पड़ा कि पशु चिकित्सा और पशु पालन विभाग में बैठे अधिकांश डॉक्टर महीनों से गांवों, जनपदों, विकास खंडों की पशु चिकित्सालय खोलते ही नहीं हैं, 90% यहां बैठे चिकित्सक जिला मुख्यालयों में डटे रहकर खानापूर्ति कर वेतन तो ले ही रहे हैं। साथ ही सन 2005 से स्वीकृत होने वाला प्रदेश भव के बजट जो रुपए 300 से 500 करोड़ के स्तर पर आ गया है हजम करने के लिए कागजी खानापूर्ति कर हजम कर जाते हैं।

इंदौर-उज्जैन के संयुक्त संचालक को सूचना के अधिकार में पत्र भी दिए गए पर वहां बैठे सरकारी पशुओं को नोंच कर खाने वाले गिद्धों ने जवाब की अपेक्षा मामलों को उलझाया, पर जानकारी किसी संयुक्त संचालक के साथ जिला पशु पालन एवं चिकित्सा अधिकारी ने नहीं दी। आखिर भ्रष्ट, जालसाज ये सरकारी गिद्ध जानकारी दें भी तो क्या, जहां जिलों के जिलाधीशों का सवाल है तो वो बेचारे नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की चाकरी, मीटिंग्स जानकारियों में ही इतना उलझे रहते हैं कि पशु चिकित्सा विभाग की इन कारगुजारियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, ये विभागीय जानवर उन मूकजानवरों की दवाइयों, दाना-पानी से लेकर हर सामान स्वयं ही साफ कर देते हैं। तो दुधारू पशुओं की घटती संख्या दुर्बलता पर ध्यान देने का समयही नहीं मिलता। स्वाभाविक, दुग्धोत्पादन तेजी से सिमटता जा रहा है और नकरी दूध का कारोबार चारों और पैर पसारता जा रहा है।

समयमाया के श्री अजमेरा ने जून 09 में सूचना के अधिकार में पत्र देकर दूध के संबंध में जानकारी मांगी थी, अमूल और सांची के पिछले तीन वर्षों में कितने नमूने लिए तो मालूम पड़ा पूरे म.प्र. में पिछले 15 वर्षों से सांची दूध के खाद्य एवं औषधि विभाग ने कोई नमूना ही नहीं लिया, वही हाल अमूल का भी था, इसकेबाद यही प्रश्न विधानसभा में भी उठवाया गया था,वहां भी सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले 10वर्षों से सांची और अमूल के नमूने नहीं लिए गए।

आखिर पूरे म.प्र. के दुग्ध संघ मुखैरे और भिखारी किस्म के अध्यक्षों और सदस्यों से भरा पड़ा है, बाद में प्रबंध संचालकों, अधिकारियों, कर्मचारियों सभी का एक सूत्रीय कार्य कम होता है, दुग्धसंघों में सहकारी/सरकारी दुग्ध संघ की बगिया में जितना लूट सके, तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब नौकरी जाएगी छूट। इंदौर के हरामखोर एमडी दारूवाला को ही लें 5 से ज्यादा वर्षों से कुंडली मारे बैठा है, पर सहकारिता मंत्री को भी महीना मिल रहा है तो क्या जरूरत है। फिर प्रदेश के सभी दुग्ध संघों में ट्रांसपोर्टरों की जालसाजियों से लेकर हर कदम चाहे वो दुग्ध खरीदी हो, पाउडर खरीदी, दुग्ध उत्पादन में पैकेजिंग में लगने वाली टनों से पालिथीन की थैलियां हो, प्लांट की बिजली खपत हो, प्लांट मेटीनेस हो, गाड़ियां, दुग्ध वितरण हो, सभी में जालसाजों का अड्डा है। इन सबके बाद समाचार पत्रों का मुंह बंद रखने के लिए विज्ञापन बांटने से लेकर उल्टे ही थैलियों पर ही भास्कर,कभी नई दुनिया का, कभी राज एक्सप्रेस का विज्ञापन चिपका कर येनक्रेन प्रकारेण मुंह बंद रखे जाते हैं। ताकि वहां बैठे जालसाज शूकरों,1% सच्चाइयां भी कोई न छाप सके। वैसे भी दैनिक समाचार भांडो की फौज का नाम है जो पैसे के लिए नारी जो कि मां भी है, नंगा करने करने से नहीं चूक रहा है तो बाकी तो सब बकवास है।

इंदौर, ग्वालियर, भोपाल दुग्ध संघ 80% पाउडर का तैयार किया हुआ दूध 200 मि.ली., 100% स्किम्ड शक्ति 80% और गोल्ड में भी 70% पाउडर का दूध पैक कर रहा है। रीवा, उज्जैन, जबलपुर, सागर, 200 मि.ग्रा. का 100% पाउडर का और 50% गोल्ड पाउडर मिला हुआ तैयार करके बेच रहे हैं। मात्र शासकीय अधिकारियों के **शेष पेज 7 पर**

सबसे भ्रष्ट ...

पेज छह का शेष

निवास पर 100% दूध शुद्ध बेचा जाता है। भोपाल में मंत्रियों के, अधिकारियों के निवास पर 3000, 400 ली. दूध शुद्ध बेचते हैं। वह भी कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों और अधिकारियों के निवास पर भी शुद्ध दूध बेचा जाता है बाकी जनता के जानवरों को शुद्ध नकली पाउडर का तैयार किया हुआ दूध बेचकर भी ये शूकरों की फौज शुद्ध और ताजे दूध के विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित ही कर रहे हैंस, जहां तक 8%, 6% फेट का सवाल है तो वो शुद्ध बकवास है। अगर हरामखोर, दुग्ध संघ के अधिकारियों से लेकर जिलाधीशों जो कि इन संघ के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। 1% भी ईमानदारी होती तो इन दुग्ध संघों के सभी उत्पादों के नमूने स्वयं भिजवाते ये शूकरों की फौज तो उल्टे ही खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक यदि नमूने लेने का प्रयास भी करें तो तत्काल हरामखोर कलेक्टरों के ही फोन घनघनाते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कलेक्टर धमकी देते हैं कि तेरी औकात कैसे हुई, तुझे मालूम है कि दुग्ध संघों में जिलाधीश पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात उसके मातहतों के सभी अपराध क्षम्य होते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि नगर निगमों, पालिकाओं के खाद्य निरीक्षक क्या करते हैं वो हरामखोर श्वानों की फौज केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम महीने की 1 से लेकर 10 तक दूधियों से अपने-अपने क्षेत्र में वसूली करते हैं।

यही हाल खाद्य एवं औषधियों के श्वान खाद्य निरीक्षकों की फौज करती है कि महीने की वसूली करो और तान कर सोओ, पूरे म.प्र. और देश का यही हाल है, देवास की खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल तो म.प्र. में एकमात्र पेकर और वितरक अमूल दूध जो गुजरात से आता है और देवास की प्रीमियर मिल्क फूड प्राडक्ट्स से पेक होता है। से रुपए 25000/- महीना वसूल कर ये भ्रष्ट, मक्कार, चुप रहती है। इस फैक्ट्री का मालिक अग्रवाल भी भरी गर्मियों में विशुद्ध नकली दूध पेक करके पिछले 7वर्षों से बेच रहा है। चूंकि गुजरात में और म.प्र. दोनों में उसके नमूने भरवा कर जांच करवाने का जोखिम नहीं उठाता। भरे अप्रैल, मई और जून के पहले दो सप्ताह में ये 50% असली और 50% नकली दूध में बेचता है। जहां तक दुध के स्तर का सवाल है तो अमूल का स्तर सांची से बेहतर होता है। बेशक सांची के दूध, मट्ठा, आइस्कीरम, मीठा दूध सबका स्तर बेहद घटिया होता है, दूसरा जब कलेक्टर पदीय अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है सांची के सभी दुग्ध संघों में लूटमार मची है तो मुफ्त का रोज 5 ली. शुद्ध दूध के साथ महीना भी पहुंचता ही है तो उन श्वानों की बला से कि जनता के साथ कैसे डकैती हो रही है।

इंदौर में ही यदि 6 लाख ली. की. रुपए 25ली का औसत भी लें तो रुपए 1 करोड़ 50 लाख का नकली दूध बेचा जाता है नगर निगम के खाद्य निरीक्षकों की कमाई हर माह रुपए 2 से लाख इन दूधियों से ही होती है। खाद्य एवं औषधि विभाग की श्वानों की फौज जिसकी अगुवाई सचिन लोंगरिया करता है, जिसमें निरीक्षक और शामिल है रुपए 2 लाख प्रतिमाह से ज्यादा कमा रहे हैं। इन हरामखोरों की वसूली का ही नतीजा है कि चारों तरफ नकली दूध खाद और डिटर्जेंट वाले की भरमार है। यदि जिलाधीश को जरा भी चिंता है तो क्यों नहीं करवाता कि कहां खाद और डिटर्जेंट जरूरत से ज्यादा बिक रहा है। गांवों में डिटर्जेंट गांव की आबादी के मान से प्रति व्यक्ति 50 ग्राम से ज्यादा डिटर्जेंट कहां उपयोग हो रहा है। क्या गांव की सोसायटीयों, खुला यूरिया बेचने वाले मार्च, अप्रैल, मई में भी यूरिया का उपयोग कौन कर रहा है, तीसरा गांव में कुल पशु कितने हैं, उसके 40% के दूधारू पशु 2 ली. से ज्यादा दूध बेच रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ सकता है नकली दूध कहां से, कितना आ रहा है।

खनिज विभाग में निरीक्षकों और अधिकारियों की लूट के चलते-

मात्र 10% राजस्व ही आता है शासन के खाते में

भोपाल। म.प्र. के खनिज विभाग में भी चारोंतरफ लूट और खनिज माफियाओं, ठेकेदारों की जालसाजी का बोलबाला है। जिन्हें हर जिले में बैठे खनिज निरीक्षकों से लेकर अधिकारियों और जिला अधिकारियों व जिलाधीशों को पूर्ण अंध संरक्षण मिलता है। जितना कुल राजस्व रायल्टी से शासन को मिलता है। जो वास्तविक उत्खनन की रायल्टी की कीमत का मात्र 10%ही होता है। शासन को मिलने वाले राजस्व के बराबर का राजस्व से डेढ़ से दो गुना ये हरामखोर राजस्व निरीक्षक ही डकार जाते हैं। जिसके बाद फिर खनिज अधिकारी, जिला अधिकारी से लेकर उपजिलाधीश और जिलाधीश का भी हिस्सा होता है। इसके बाद संचालक, सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री भी डकारते हैं।

बीओटी ठेकेदारों ने 5% भी जमा नहीं की, सूचना अधिकार में झूठी जानकारियां दीं

प्रदेश की नदियों की रेत से लेकर गिट्टी, पत्थर की खदानों स लेकर कोयला, स्लेट पत्थर, लौहा, तांबा, माइका से लेकर हीरा तक प्रदेश में निकलता है। इसके विपरीत कुल कितनी आय खनिज और विक्रय रायल्टी से हो रही है न तो म.प्र. का खनिज विभाग बताता है न ही खनिज निगम, बस विभाग चल रहा है कैसे चल रहा है, किसी को नहीं मालूम, आखिर म.प्र. के बजट में खनिजों को उत्खनन से प्राप्त रायल्टी की आय से प्राप्त आय म.प्र. के बजट में शामिल क्यों नहीं की जाती।सारा पैसा विभाग और निगम मिलाकर ही हजम कर जाता है और खनिज निगम का अभी तक किसी ने कभी भी प्राप्तियां और व्यय के साथ चिट्ठा भी किसी ने नहीं देखा है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार म.प्र. के हर जिले में हजारों खदानें हैं। जिनमें पत्थर निकालने से लेकर गिट्टी फोड़ने और बेचने 90% धंधा अवैध रूप से चलाया जा रहा है। सरकारी भूमि जो नजूल में है। वन विभाग की है। किसानों की कृषि भूमि है में हीरे से लेकर पत्थर तक सब कुछ प्रदेश की भूमि से निकाला जा रहा है, परंतु आय कितनी हो रही है, विभाग के 99% लोगों से लेकर जनता 00.1% लोगों को भी नहीं मालूम बस बंदरबांट में ही हजम हो रहा है। अकेले पन्ना जिले की हीरा उगलन वाली धरती 90% हीरा चोरी छिपे पूरी दुनिया में जाता है। विभाग को 10% हीरे की भी रायल्टी ही मिलती है और कुछ बिक्री का हिस्सा फिर उसमें भी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी भ्रष्टाचार और लूटपाट से बाज आने से रहे।

म.प्र. में ही पिछले 5 वर्षों में म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत बनने वाली बीओटी की सड़कों में ही रुपए 1000 करोड़ से ज्यादा की रॉयल्टी घोटाला हुआ है। अकेले देवास-भोपाल में 180 कि.मी. फोर लेन सड़क जो 4 से 5 फीट तक भराई करने के बाद स्तरहीन तरीके से बनाई गई रुपए 150 करोड़ की रायल्टी म.प्र. सविनि का प्रबंध संचालक आजमगढ़िया आतंकी जिसने सड़कों पर टोल टेक्स का आतंक मचवा दिया है। सुलेमान, मु.मं. शिवराज ने ठेकेदार के साथ मिलकर हजम कर लिया, जबकि सड़क के इस्टीमेंट में वह रायल्टी मिलाकर बजट बनाकर स्वीकृत किया गया था, यहीहाल इंदौर देवास, लेबड़, रतलाम, नयागांव-मंदसौर जैसी लगभग 1000 किमी सड़कों में किया गया। सड़क फोरलेन होने से रुपए 1 करोड़ की रायल्टीके हिसाब से रुपए 1000 करोड़ का घोटाला कर सभी ठेकेदारों को रायल्टी की जिम्मेदारी यह कहकर बचा लिया गया कि वह एग्रीमेंट में ही माफ कर दी गई थी, तो हरामखोरों रायल्टी की राशि से इस्टीमेंट में कमी क्यों नहीं की गई। केवल डकारने और वसूली में टोल टेक्स वसूलने के लिए उसे वहां क्यों शामिल किया गया। यह घोटाया पूरे प्रदेश की 29 सड़कों में हुआ जो कुल 2000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। जबकि अभी मामला केवल गिट्टी और पत्थरों का ही है, जिसमें एक विभाग कीही बात की जारही है। अकेले इंदौर में ही हर वर्ष रुपए 150 करोड़ से 200 करोड़ का गिट्टी, पत्थर का कारोबार हो रहा है। भोपाल में रुपए 200 करोड़ से 300 करोड़ का अभी प्रदेश के 48 जिले बाकी है। फिर पूरे प्रदेश में गिट्टी, पत्थर, चूने, नर्मदा के बेल्ट में संगमरमर से लेकर रीवा, सतना, पन्ना बेल्ट में हीरे तक लगभग 100 किस्म के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। जिसमें लोहा, तांबा, अभ्रक, सिलिका, कोल, मीथेन गैसतक सब निकल रहा इन घोटालों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी अहं भूमिका निभाई और ठेकेदारों का लोक निर्माण, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय, जल संसाधन के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदारों को रायल्टी जमा करने की बाध्यता से सरकारी मिलीभगत और ढीलेपन से मुक्तकर दिया गया। पाठक समझदार हैं कि क्यों प्रदेश के राजस्व को चोट पहनाकर मुक्त किया गया। इसके विपरीत विभाग में सर्वोच्च न्यायालय में न तो अपील की, न ही बाध्यकारी कानून बनाए, सब भ्रष्ट,भ्रष्ट मौसेरे भाई।

सब तुले हैं...

पेज आठ का शेष

केवल विचार करना चाहिए, वरन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विकास के लिए जनहित में शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। नए कानून बनाए जाएं।हमारे भारत के प्राचीन आयुर्वेद और अन्य धार्मिक औषधीय और स्वास्थ्य से संबंधी वर्णित शिक्षा जिसमें पुरुष को 25वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन की सीख दी गई थी उसके पीछे पुरुष के सुंदर स्वास्थ्य मानसिकता शारीरिक विकास की ठोस अवधारणा ही थी। दूरस्थ आश्रमों में शिक्षा के पीछे पुरुषों के दीर्घ स्थाई पौरुष को सहेजना ही मूल कारण था।

वर्तमान परिदृश्य में सह शिक्षा 24 घंटे 7 दिन बंटता टीवी चैनलों का यौनाचार युवा पीढी को 14-15 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही स्कूल में सहपाठियों के साथ यौनाचार को आमंत्रित कर भोग लेता है। फिर ऊपर यौनशिक्षा की पैरवी देकर स्वच्छंद यौनाचार फैलाना ही है। इन सबमें सबसे पहले, सबसे ज्यादा बर्बाद होगा अतिशोषण से वो स्कूली 12 से 18वर्ष के लड़के निचुड़कर 21-22 वर्ष की उम्र तक पहुंचते- पहुंचते ही अवसाद और कुंठा के शिकार होने लगते हैं। बची खुची कसर और उस पीड़ा पर मिडिया के ये मसालेदार विज्ञापन 25-30 तक पहुंचते-पहुंचते जीवन को निरर्थक और स्वादहीन बना रहे हैं। देश की सभी माताओं की पीड़ा को कौन समझेगा।

बजट में महंगाई ...

पेज तीन का शेष

अधिकारी से जिला शिक्षा अधिकारी तक कागजों में ही खर्च होगा।

रुपए 80 करोड़ की गणवेश वितरण- रुपए 20 करोड़ की भी गणवेश बच्चों को मिल जाए तो आधे विद्यार्थियों को वर्षभर गुजर जाएगा तन ढंकने के लिए।

रुपए 50 करोड़ की पाठ्यपुस्तकें- रुपए 10 करोड़ का छपाई में कमीशन, रुपए 5 करोड़ की रद्दी बेचने से कमाई का साधन।

म.प्र. स्वास्थ्य विभाग

रुपए 1878 करोड़ स्वास्थ्य के लिए- रुपए 1500 करोड़ से डॉक्टरों से लेकर सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री तक सबके बैंकों और निवेश की हालत सुधरेगी।

जननी सुरक्षा योजना रुपए 202 करोड़ से जननी की सुरक्षा सुधरे न सुधरे लगभग 102 करोड़ से अस्पताल के कर्मचारियों, दाई से लेकर डॉक्टरों, मंत्री, मुख्यमंत्री, तक की सुरक्षा होगी। जननीयों के नाम पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्रोंसे लेकर जिला अस्पतालों तक कैसी कागजी खानापूर्ति कर धनराशि डकारी जा रही है धार जिले के जननी सुरक्षा के पत्रकों पर लगे हाथ पैर के अंगूठे बताते हैं।

रुपए 29 करोड़ दीनदयाल अन्त्योदय योजना- गरीबों की चिकित्सा के नाम पर रुपए 10 करोड़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके मातहत डकार जाएंगे जैसा कि इतिहास है।

रुपए 60करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- गरीबों की चिकित्सा कने नाम रुपए 10 करोड़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके मातहत डकार जाएंगे। जैसा कि इतिहास है।

रुपए 60 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- 10 जिलों में लागू होगी बीमा जनता का वसूली विभागीय कर्मचारियों की।

रुपए 127.09 करोड़ रा.ग्रा. स्वा. मिशन ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधरे न सुधरे, विभागीय कर्मचारियों, डॉक्टरों से लेकर सीएमओ, संचालकों से मंत्रीयों तक के स्वास्थ्य सुधर जाएंगे।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना- रुपए 200 करोड़ का आवंटन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में म.प्र. में 31-3-10 तक 34200 किमी सड़कें बनाई जा चुकी है। अभी 500 आबादी से ऊपर के लगभग सभी गांव राज्य मार्गों से जोड़े जा रहे हैं। अंतिम चरण में 250 आबादी वाले गांवों को भी राज्यमार्गों से मार्च 2015 तक जोड़ दिया जाएगा। अर्थात मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में 2010-11 के बजट में वर्तमान सरकार के भ्रष्ट अधिकारी झाड़ू, पोंछा मार कर मुख्यमंक्री शिवराजसिंग का बोर्ड लगवाकर उद्घाटन करवाएंगे और ताली बजाकर सारा बजट हजम कर जाएंगे, क्योंकि ग्रामों में 250 की आबादी 2015 तक जोड़कर 70000 किमी सड़कें पीएमजीएस वाई मेंही बना दी जाएंगी। तो राज्य सरकार के पास बनी हुई सड़कों पर झाड़ूपोंछा मारकर उद्घाटन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। ग्रामीणों के वोट कबाड़ने और राज्य की जनता के धन को हड़पने का नुस्खा नायब है फिर जो तथ्य सदन में रखे गए हैं उसकी सत्यता यह है कि सामान्य 500 से कम आबादी के और आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए रुपए 200 करोड़ को सीधा कागजी कार्यवाही दिखा कर हड़पा ही जाएगा। बाकी कच्ची मुरम की सड़कें जो अभी भी हैं फिर नरेगा की योजना के काम करवा और दिखा कर भुगतान भी नरेगा से ही होगा जो जिला जनपद पंचायत के माध्यम से ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा को देकर करवा लिया जाएगा।

मप्र लो.नि.वि ...

पेज पांच का शेष

पट्टियां जो पक्की सड़क से दोनों और समतल होकर कच्ची मुरम से बराबर रखरखाव की जानीच ाहिए ताकि वाहन चालक वाहन को आसानी से जरूरत पड़ने पर साइड दे सके, अन्यथा उस पर खड़ी कर सके, जबकि बीओटी की सिंगल लेन रोड पर टोल वसूली होते हुए 3-4 वर्ष से ज्यादा हो जाने के बाद भी अभी तक पक्की सड़क से तल नहीं मिलाया गया न ही उनकी भराई की गई, जिसमें हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, बैतूल, इंदौर, इदिलाबाद जिसमें अवैध रूप से दो स्थानों पर इस हरामखोर की देखरेख में अवैध टोल वसूल हो रही है। चार वर्षों से पैसों केा दम पर मामला उच्च न्यायालय में अटका रखा है। इन सबके भ्रष्टाचार में ये श्वान भी चुप इसीलिए है, क्योंकि इसने उसके पैसे में भी आधा-आधा कर लिया और कर रहा है।

समयमाया के इस सुलेमान के भ्रष्टाचारों को प्रकाशित करन का ही परिणाम था कि केंद्रीय भूतल एवं पोल परिवहन मंत्री कमलनाथ ने सारे राष्ट्रीय राजमार्गों के इसके द्वारा जारी की गई निविदाओं को एक झटके में रद्द कर दिया, इससे चिढ़ कर ही राष्ट्रीय राजमार्गों के सारे 15 संभाग बंद करने पर तुल गया है और बंद करने केा आदेश जारी कर दिए गए। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रुपए 100 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट लेने से स्पष्ट मना कर दिया है। ये पूरा लोक निर्माण मंत्रालय यहां भी मुंहकी खाएगा, क्योंकि 5416 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रदेश की सड़कों जिसमें कई सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग सी छीन कर राज्य राजमार्ग में घोषित कर उन पर बीओटी लगा दी है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंदौर-भोपाल 180 किमी जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 89 था इ पर भी ठेकेदार ने बिना सील कोट किए ही 2 स्थानों पर बीओटी अवैध रूप से वसूलना शुरू कर दी है। इसके साथही सुलेमान ऐसे सभी ठेकेदारों के सात मिलकर म.प्र. शासन को अरबों रुपए की रायल्टी जो गिट्टी, पत्थर, मुरम की मिलना चाहिए थी ठेकेदारों से भुगतान नहीं करवा रहा है, ये हाल लेबड़-रतलाम-मंदसौर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग था छीन कर राज्य के राजमार्ग में बदलकर फोरलेन बनवाया गया जिसमें शासन को रुपए 50 करोड़ की रायल्टी मिलना चाहिए थी कुछ लाखों में ही मिली जबकि वसूली वो पूरी जनता से कर रहा है।यही हाल देवास-भोपाल की 4लेन बीओटी में भी हुआ इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र देवास और सीहोर जिले का था। इन हरामखोर खनिज विभाग वालों ने न तो जानकारी सूचना के अधिकार में दी और ठेकेदार के साथ मिलकर शिवराज, सुलेमान की बंदरबांट के साथ ही खनिज विभाग ने भी चुपचाप करोड़ों रुपए डकारे, यही हाल इंदौर-उज्जैन में तराह के शूकर कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों का निर्माण भर करना था बेशक वर्तमान में इस मुर्ख ने लोक निर्माण विभाग को कमजोर और बंद करने के दृष्टिकोण से वर्षों से पूर्ण हो चुकी सन 2007 तक की लगभग 20000 किमी सड़कें जो गारंटी की अवधि पूरी कर चुकी है और रखरखाव में आ चुकी है। भी जानबूझकर म.प्र. ग्रा.स.वि. प्रा.को ही सौंप दी यदि ये बुद्धिमान होता तो वो सड़कें लोक निर्माण विभाग को दिलवा कर कमाई का एक नया घर खोलकर उसमें भी मोटा कमीशन डकारता, जबकि उसका पैसा केंद्र सरकार और मंडी शुल्क से ही मिलजाता। वैसे भी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस का पूरे देश का हर अधिकारी उच्च स्तरीय नीच, भ्रष्ट, अय्याश, सफेदपोश डकैत होते हैं जो राष्ट्र के जन धन की नोंच खसोट करके राष्ट्र की कीड़े मकोड़े रूपी जनता को गाली बकते, फुफकारते हुए अपने तरीके से मारते हैं। अंग्रेजों के असली संकर वंशज हैं ये।

साप्ताहिक समय माया

वर्तमान दृष्य और श्रव्य मीडिया धन के लिए छाप रही विज्ञापन

सब तुले हैं युवा पीढ़ी के पौरुष की हत्या करने

न्यायालय प्रशासन घोर निंद्रा में किसी को चिंता नहीं भविष्य की

भारत का वर्तमान बड़े से बड़ा प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों कासमूह से लेकर क्षेत्रीय प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, दृष्य टीवी श्रृंखलाएं फिल्में सब न केवल अश्लीलता परोस कर यौन उत्तेजना पैदा कर युवौओं को जवान होने से पहले ही बूढ़ापे और नपुसंकता की तरफ धकेल रहे हैं। यह चिंता उन माताओं की है जिनके युवा होते पुत्र 10 से 25 वर्ष की उम्र में है। 24 घंटे 7 दिन टीवी चैनल्स, समाचार पत्र न केवल नग्न चित्रों, दृश्यों, वीडियो के प्रसारण में आगे से आगे रहकर यौन उत्तेजक चटपटी सामग्री भी परोस रहे हैं जिनमें किस फिल्मी वारांगना ने कहां अपनी स्तन चिकित्सा करवाकर सिलिकॉन भराई कराई किस चुबंन दृश्य में किस नौटंकी बाज से कितनी देर अपने होठों पर होंठ रखकर चूसा तक का भारी वृहत विवरण परोसा जा रहा है, दूसरी ओर अनावश्यक गर्भधारण रोकने, गोलियों, कंडोम के विज्ञापन आलिंगन बद्ध हो,यौनाचार के साथ दिखाए जा रहे हैं। फिल्मं में आइटमसांग के नाम पर सामूहिक यौनाचार और नग्नता का भौंडा प्रदर्शन कंडोम, अनावश्यक गर्भाधान को रोकने की गोलियों, के टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन जो परिवार के बीच टीवी कार्यकर्ताओं में दिखाए जाते हैं और 6-8 वर्ष के बच्चों के कौतूहल, जिज्ञासा जगाते हैं, बिलकुल भी आपत्तिजनक नहीं लगते हैं। आखिर पूरी केंद्रीय सरकार अमेरिकी इशारे पर राष्ट्र की युवा पीढ़ी को स्कूलों और कालेजों में स्वच्छंद यौनाचार के उलझकर किस प्रकार बर्बाद कर रही है, उसका एक सीधा सा उदाहरण हैं सत्ताधीशों की सोच है, कि युवा पीढ़ी को उसके शैशव काल से ही उसमें उलझा दो ताकि उनके कुकर्मों देश को गिरवी रखने, बेचने, कमीशनखोरी की तरफ किसी की निगाहें ही न पहुंचे और वो अपने भ्रष्टाचार करते हुए राष्ट्र की सत्ता के दम पर पर्यावरण लूट खसोट करते हुए सत्ता भोग सकें।

मीडिया दृष्य और श्रव्य की अश्लीलता, यौन उच्छश्रृंखलता समाज में आता पश्चिमी खुलापन,स्वच्छंद यौनाचारिता न केवल समाज में न केवल बढ़ते तलाकों काकारण घरों के और समाज के विघटन का कारण भी बन रही है। इस परिदृष्य में बर्बाद हो रहा है तो पुरुष और उसके पौरुष का शोषण और हत्या हमारी समाजक ो किस पतन की और ले जा रहा है फिर दूसरी तरफ मीडिया में छपते लिंग मोटाकरने, लंबा करने के जर्मन यंत्र, तेल, तिले स्त्रीयों के स्तन बढ़ाने, कड़े बनाने, ढीली यौनि को सिकाड़ने, स्त्रीत्व को निखारने के लिए विज्ञापन हमारी युवा होती पीढ़ी कुंठित कर बर्बाद कर रही, परंतु समाचार पत्रों के धूर्त मुखैरे चाहे उसमें भास्कर,लोकस्वामी, प्रभात किरण, अग्निबाण, पत्रिका, राज एक्सप्रेस, नई दुनिया, जैसे मालवा के दैनिक हों या टीवी चैनल युवा पीढ़ी के मन में हीनता उत्पन्न कर रहे हैं और युवा पीढी लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा अपने आप को आकर्षक बनाने और दम मारने के लिए आकर्षित होकर इन भ्रमित करने वाले विज्ञापनों में धन, समय और शरीरकी बर्बादी के कारण भी बन रहे हैं भ्रष्ट धन के मुखैरे मिडिया को इस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे वर्तमान की पीढ़ी का भविष्य क्या होगा।

ऐसे सभी विज्ञापनों को भारतीय विज्ञापनप्रकाशन आचार संहिता (मेडिकल कोड एंड इथिक्स ऑफ पब्लिकेशन आफ एडवरटीजमेंट एक्ट (1956) में पूर्णतः न केवल प्रतिबंधित किया हुआ है। वरन ऐसे झूठे भ्रामक चिकित्सीय विज्ञापनों जो लिंग वर्धन कड़ा मोटा बनाने, स्त्रीयों के स्तन बड़े करने, ठोस बनाने, यौनि सिकोड़ने, कड़ी करने आदि से संबंधित है जनता को झूठे चिकित्सकीय वादे करने, भ्रमितकर माल बेचने, पैसा इकट्ठा करने आदि के लिए इस कानून में तो पूर्ण व्यवस्था है ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में भी ऐसे सभी विज्ञापन देने, विज्ञापन एजेंसियों,प्रकाशकों सभी को गिरफ्तारकर मुकदमा चलाने और 7वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इन सब पर स्वमेव ही संज्ञान लेकर विज्ञापनदाता एजेंसी और प्रकाशकों न्यायालय में हाजिर कर दंड दे सकता है। परंतु सभी वकील स्त्री-पुरुष स्वयं न्यायाधीश, स्थानीय जिलाधीश, उपजिलाधीश, सहायक जिलाधीश, चाहे तो ऐसे समाचार पत्रों के इस आधार पर पंजीयन रद्द करने की अनुशंसी भारतीय समाचार पत्र पंजीयक, समाचार पत्र, पंजीयन कार्यालय नई दिल्ली को भेज सकते हैं। परंतु सब अपनी ही संतानों देश की युवा पीढी को यौवन अवस्था तक पहुंचने से पहले ही कम से कम युवाओं के पौरुष की हत्या करवाते हुए नपुसंक बनाने पर तुले हैं। मिडिया अर्थात बर्र के छत्ते में कौन हाथ डाले, जो डाले उसके विज्ञापनों को रोकने की प्रशंसा तो क्यों करेंगे वरन उसके पीछे उल्टे ही पड़कर उसे पदच्युत करवाने, स्थानांतरण करवाने किसी भी मामले में उसकी जांच बिठवाने के अवश्य पीछे पड़ जाएंगे।

युवा पीढ़ी की बुद्धिमान, शिक्षित और गंभीर सोच समझ वाली माताओं की पीढ़ा अपने बेटों के पौरुष की अप्रत्यक्ष रूप से होती हत्या और उनके सुखद वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को जो लेकर हैं निःसंदेह बेहद गंभीर समस्या है। जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय, विधि मंत्रालय मानव संसाधन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को गंभीरता से न

अपने ही कुकर्मों और भ्रष्टाचार से भयाक्रांत भाजपा

इसलिए डरपोक नहीं पूरा करते वि.सत्र

१० दिन का सत्र ५ दिन में निपटाने की तैयारी थी, २२ दिन सत्र मात्र १३–१४ दिन में खत्म करने की तैयारी

भोपाल। म.प्र. का मुख्यमंत्री शिव और उसका गिरोह कितना भी ईमानदार होने का पाखंड करे न केवल स्वयं घोर भ्रष्ट है वरन पूरे मु.मं. कार्यालय में इकबाल सिंह बैस महाजालसाज से लेकर जनपदों और ग्रामीण पंचायतों के सरपंचो और सचिवों तक भ्रष्टों का मकड़जाल फैला हुआ है। मुख्यमंत्री की मुख मैथुनी घोषणाएं ईमानदारी से काम करने की और काम सत्यता में कदम-कदम भ्रष्टाचार से लूट खसोट का चेहरे पर नकाब नाम शिव की तरह भोले होने का काम पूरे राक्षसों की तरह, हर कदम शासकीय भ्रष्टाचार और लूटपाट का, जहां निगाहें उठाओ जटाओ से भ्रष्टाचार की गंगा हिलौरे मारती हुई भोपाल से लेकर 50 जिलों की ग्राम पंचायतों तक बहरही है। शिव की साधना बन गई है, हर पल चहुं दिश भ्रष्टाचार यही कारण है कि ये दिग्गी दानव के भ्रष्टाचारों और जालसाजियों से ज्यादा शातिर सिद्ध हो रहे हैं। दिग्गी दानव तो भ्रष्टाचार का दिग्विजय था, परंतु अधिकांश विधानसभा सत्रों को वो पूरा करता था, सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाते थे। पूरी सुनवाई होती थी।

ये मुंह में राम नाम जपने वाले, हर सरकारी माल कानून अपनी बपौती मान यहां तक कि विधानसभा का पिछला सत्र 10 दिन का था उसे 5 दिन में ही पूरा करने की तैयारी थी जिसे समयमाया ने पूर्व सत्र को जालसाजी पूर्ण तरीके से बंद करने के पूर्व ही प्रकाशित कर दिया था। इसलिए 7-8 दिन तक खींचना पड़ा था।

अब जबकि प्रदेश का बजट सत्र जो फरवरी 22,10 से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल तक चलना चाहिए था जो कि मात्र 22 दिन का था जिसमें 17 दिन की छुट्टियां थी को भी घटाकर ये भ्रष्टाचारियों और सफेदपोश वैधानिक डकैतों का गिरोह उसे 19 मार्च या 22 मार्च तक समाप्त करने की तैयारी में है। यह बात 8 मार्च को ही निश्चिय कर ली गई और विपक्ष की नेता श्रीमती जमुनादेवी को ले देकर समझा लिया गया, ताकि 19 मार्च या 22 मार्च तक सत्र यह कहकर कि काम नहीं है, समापन किया जाए, वो चुपचाप घड़ियाली गुस्सा दिखाकर और पूंछ पटक कर स्वीकार कर लेगी सत्र समाप्त, जबकि बजट में आगम आय से लेकर व्ययों तक में हर कदम-कदम जालसाजियों का अंबाल लगा हुआ है। मु.मं. ग्राम सड़क योजना पर रुपए 200 करोड़ खर्च की व्यवस्था क्यों की गई जबकि वह कार्य नरेगा में केंद्र के रुपए 5000 करोड़ और राज्य के रुपए 584 करोड़ में हो गया है किया जा सकता है। फिर 48 जिलों में भी महिला बाल विकास में जिला मुख्यालयों से लेकर विकास खंडों व जन पंचायतों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर विकासखंड, म.बाल.वि. अधिकारी तहसीलों और जिला कार्य अधिकारी सभी भ्रष्ट राक्षसियों का गिरोह सारी जालसाजों की पलटन रजिस्टरों में 25 से 100% तक बच्चों की झूठी सूची बनाकर हजम कर रही है, पर कोई देखने, सुनने वाला भी नहीं। पूरे प्रदेश में हर वर्ष 2000 करोड़ से ज्यादा रायल्टी घोटाला होता है। 50% वाणिज्यकर औसतन 30% आबकारी, 30% स्टाम्पस की आय, रुपए 3000 से 5000 करोड़ तक का भूमि घोटाला, लो.नि.वि. में 50% का काम, जल संसाधन में 25 से 35% का काम, लो. स्वा. यांत्रि. वि. में 60% का काम, ग्रायया.वि. में 40% का काम, नरेगा में 25% का काम, स्वास्थ्य विभाग में 25% का वास्तविक खर्च, नगर निगमों में 25 से 35% का काम महिला बाल विकास में 25% कृषि वि. में 40% का काम और औसतन सभी शासकीय विभागों की कहानी है बाकी सब पैसा हजम।

जब एक बार 25 फरवरी 10 का बजट पेश किया गया था तो फिर 9मार्च को रुपए 6225 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश क्यों किया गया? जो कि प्रदेश को 31-3-10 तक प्राप्त आ पर 4588 करोड़ का भार डालेगी। इसमें पुनः बिजली, पानी व सड़क के लिए बजट आवंटित किया गया यही कारण था कि इस बजट सत्र को मार्च के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ किया गया, जबकि हो हल्ला न मच सके जब एक बार बजट में वर्ष भर का प्रावधान कर दिया गया तो पुनः अनुपूरक अनुमानित बजट पेश कर क्यों राशि का आवंटन किया, ताकि इसे ऊपर ही ऊपर आईएएस और मंत्री मिलकर डकार सकें। अधिकृत जानकारी के अनुसार पोलीटेक्निक संस्थाओं के लिए 43 करोड़, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 34.80 करोड़, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 15.08 करोड़ और पर्यटन अधोसंरचना निर्माण के लिए 11.84करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

फिर भाजपा के शिव के ईमानदारी के पाखंड के गिनने के लिए शिव निवास में कितनी नोट गिनने की मशीनें लगी है क्या ये अनुपूरक बजट इसलिए दूसरी बार स्वीकृत किया गया, ताकि उन मशीनों में जंग न लग जाए, जब ये सब करना ही है तो दिग्गी दानव की तरह अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार भी जमकर करो तो उसका सामना करने की हिम्मत भी 5वर्ष में विकसित कर लेना चाहिए था। दुनिया का हर आदमी दुनिया से तो झूठ बोल कर बच लेता है परंतु अपने आप से कैसे बचे क्या उसी भ्रष्टाचार की स्वयं की परछांई से भी इतना डर लगता है कि सत्र हमेशा समय पूर्व बंद कर मैदान छोड़कर भागना पड़ता है।

मध्यमवर्गीय...

पेज एक का शेष

प्रबंध संचालक से लेकर बाबू, चपरासी तक सफेदपोश डकैतों का अड्डा बन चुकी है। हर कदम सेवा शुल्क के नाम पर पूरी बैंकिंग में लूट मची है, जनता के साथ तो ये पैसा क्यों दिया जा रहा है। पेट्रोल-डीजल पर 32% राज्य सरकार और 32% केंद्र सरकार जो कर वसूल रही है साथ ही 2% शिक्षा, 2% सड़क निर्माण और सुधार 1% अन्य कर वसूल कर 69% की जो वसूली कर रही है इसके बाद भी ये सत्ताधीश सड़कों पर बीओटी लगाकर वसूली कर रहे हैं।

लोकतंत्र नहीं अब लूटतंत्र बन चुका है जिसका काम जनता से लूटकर उन्हें रोटी भी ढंग से न मिल सके और ये आने वाली 50पीढ़ियों की व्यवस्था करें, फिर भी न रखा जाए तो स्विस बैंको अमेरिका, यूरोप की बैंकोंसे जमा करें और यूरोप वाले इस काली कमाई को बैंकों में जमा करें और यूरोप वाले इस काली कमाई को बैंकों को दिवालिया कर हड़प लें, धन्य हैं सत्ताधीशों तुम गिद्धों से ज्यादा नीच, शूकरों से ज्यादा गंदे हो, गिद्ध और शूकर तो गंदे होने पर भी मानव का भला ही करते हैं और

तुम अपनी ही जनता के मुंह से निवाला छीनकर विदेशों में जमा करते हो, जनताका धन,जन कल्याण के लिए है, लूटकर विदेशी बैंकों में जमा करने के लिए नहीं, इकट्ठा कितना भी कर लो खाओगे एक आम आदमी की तरह, सुबह-शाम चार रोटी ही और सड़ते हुए शूकरों, मनमोहन, प्रणव , शरद पंवार, कब्र में टांगे लटक रही है। तो फिर किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, बहुत जल्द तुम्हारी आने वाली रातें अंतिम हो जाएंगी। फिर सुबह नहीं होगा, पर जनता के 120 करोड़ का सवेरा आवश्य होगा, जब तक उनका जीवन है क्यों अपनी गिद्ध नोंच से उन्हें भूखा मारने पर तुले हो।

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803